जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 341 प्रभात कोटा, बुधवार 24 सितम्बर, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

विश्वास नहीं जम पा रहा, भारतीय प्रोफैशनल्स का ट्रंप की ''इमिग्रेशन'' नीतियों पर

नवीनतम नीति के अनुसार, अमेरिका उन विदेशी प्रोफैशनल्स को प्राथमिकता देगा, जिनका वेतन भारी है और शैक्षणिक योग्यता भी अधिक है

- अब तक एच-1बी वीज़ा, लॉटरी सिस्टम से दिया जाता था, जिसमें कम या भारी तनख्वाह पाने वालों को एक ही पलड़े में रखा जाता था, लॉटरी निकालने से पहले।
- यूनएन की 80वीं जनरल असैम्बली को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने विदेशी प्रोफैशनल्स को वीज़ा देने की नई नीति को उजागर किया।
- ट्रंप ने अपने भाषण में यूरोपीय देशों की भी काफी आलोचना की, कि इन देशों ने गैर-कानूनी तरीके से सीमा पार से आने वाले वर्कर्स की समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और इसीलिए ये यूरोपीय देश भारी संकट में हैं।
- भारतीय आईटी प्रोफैशनल्स व अमेरिका की बड़ी-बड़ी आईटी कम्पनियां, आपस में पूर्णतया सहयोग कर रही हैं, ट्रंप की नित्य, रोज-रोज बदलती नीतियों के साथ एडजस्ट करने के लिए। जितना आवश्यक भारतीय आईटी प्रोफैशनल्स के लिए अमेरिका में नौकरी मिलना है, उतना जरूरी अमेरिका की आईटी कम्पनियों के लिए भारतीय वर्कर्स को नौकरी देना है, क्योंकि अगर विदेशी आईटी प्रोफैशनल्स नहीं हों तो इस सैक्टर के लिए अमेरिका में जीवित रहना उतना ही मुश्किल हो जायेगा।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 सितंबर। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के भाषण ने यह भरोसा नहीं दिलाया कि अमेरिका एच-1बी वीज़ा रखने वाले भारतीय प्रवासियों का स्वागत करेगा। इसके बजाय यह धारणा और मजबूत हुई कि यह राष्ट्रपति अमेरिका में विदेशी कामगारों की मौजूदगी को सीमित करने पर तुला हुआ है।

ट्रंप प्रशासन ने अचानक ही हर एच-1बी वीज़ा आवेदक पर प्रति वर्ष 1,00,000 डॉलर की भारी फीस लगाने की घोषणा कर दी। व्यापक विरोध के बाद सरकार ने सफाई दी कि बढ़ी हुई वीज़ा फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी और वर्तमान वीज़ा धारकों को बिना किसी रुकावट के काम जारी रखने दिया जाएगा।

आज ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीज़ा के आवंटन की एक नई प्रणाली की भी घोषणा की, जिसमें आवेदकों के वेतन और शैक्षिक योग्यता को जोड़ा जाएगा। नई योजना के तहत अब वीज़ा लॉटरी प्रणाली से नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अब ऊँचे वेतन वाली नौकरियों और अधिक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी।

इरादा यह है कि केवल बहुत ऊँचे वेतन वाले पदों पर कार्यरत लोगों की ही इन वीज़ाओं तक आसान पहुँच मिले

(शेष पृष्ठ 5 पर)

आरपीएससी में तीन सदस्य नियुक्त

- पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. अशोक कलवार तथा शिक्षाविद् डॉ. सुशील कुमार बिस्सू सदस्य बने।

अजमेर, 23 सितम्बर। राजस्थान लोक सेवा आयोग में तीन नये सदस्य नियुक्त किए गये हैं। पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी के अलावा, डॉ. सुशील कुमार बिस्सू व डॉ. अशोक कुमार कलवार सदस्य बने हैं।

आयोग में अभी छह सदस्यों के पद खाली चल रहे थे। अब तीन नये सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद, आयोग सदस्य के दस में से सात पद भर गये हैं, पर तीन पद अब भी खाली हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में राजस्थान लोक सेवा आयोग में यह दूसरी नियुक्ति है। इससे पहले, पूर्व डीजीपी यूआर साहू को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हेमंत

(शेष पृष्ठ 5 पर)

राहुल गांधी की ''यात्रा'' ज्यादा रास नहीं आ रही आरजेडी को

आरजेडी का मानना है, यात्रा ज्यादा सफल हुई तो कांग्रेस और अधिक सीटें मांगेगी और इससे तेजस्वी को मु.मंत्री बनाने की कोशिश में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं

- उदाहरण के लिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 टिकट देने पड़े थे, महागठबंधन को, पर, कांग्रेस जीती केवल 19 सीटों पर।
- कांग्रेस का जवाबी तर्क है, उसे अधिकतर वो सीटें दी गई थीं, जिन पर महागठबंधन का जीतना असंभव था। अतः इस बार कांग्रेस का ख्वाब है, चाहे पाँच-सात टिकट कम मिलें, पर वो सीटें मिलें जहाँ वह मजबूत है और जीत सकती है।
- बहरहाल, शायद अभी कांग्रेस व आरजेडी अपने-अपने रास्ते पर अलग-अलग चल रहे हैं।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 सितंबर। प्रतीकात्मक रूप से यह अवसर बहुत बड़ा है, 1940 के बाद यह पहला अवसर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की विस्तारित बैठक को बुधवार को पटना के सदाकत आश्रम स्थित पार्टी मुख्यालय में हो रही है। राहुल गांधी की हालिया ''वोट अधिकार यात्रा'' की पृष्ठभूमि में, कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था सीडब्ल्यूसी की इस ऐतिहासिक स्थल पर बैठक नवंबर में होने वाले चुनावों को लेकर पार्टी के उत्साह का संकेत मानी जा रही है।

वस्तुतः यह बड़ा आयोजन एक राजनीतिक दबाव के तरीके के और कुछ नहीं माना जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे में अधिकतम और जिताऊ सीटें हासिल करने का अप्रत्यक्ष प्रयास है।

महागठबंधन की उभरती राजनीतिक बारीकियाँ इसकी सूक्ष्म

(शेष पृष्ठ 5 पर)

ट्रंप का ''वीज़ा खेल'' : भारत को शॉर्ट-टर्म परेशानी, पर अमेरिका को दीर्घकालीन नुकसान

इकॉनमिस्ट, अमेरिका की ग्रोथ को 2 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत रहने की आशंका जता रहे हैं

- दूसरी ओर, भारत की विशाल जानी-मानी आईटी कंपनियाँ, भारत के आईटी उद्योग टैरिफ से उत्पन्न होने वाली दिक्कतों का सामना करने के लिए काफी समय से तैयारियाँ कर रही थीं।
- उदाहरण के लिए, इन कंपनियों ने अमेरिका में ही स्थानीय वर्क फोर्स तैयार कर ली थी। अतः भारत तत्कालिक पीड़ा को, नई बिजनैस रणनीति, डिलिवरी मॉडल में तब्दीलियाँ करके बर्दाश्त कर लेगा।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का अचानक एच-1बी वीज़ा पर 1,00,000 डॉलर की भारी फीस लगाने का फैसला फिलहाल भारतीय टैक कर्मचारियों को झटका दे सकता है, लेकिन असली बड़ा नुकसान अमेरिका को होने का अंदेशा है। भारत, जहां एच-1बी वीज़ा धारकों की सबसे बड़ी संख्या है, को शुरुआती परेशानी ज़रूर होगी, पर अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि इससे अमेरिका को अपनी आर्थिक वृद्धि में रुकावट आने का खतरा है, टैक्नॉलजी में उसकी प्रतिस्पर्धा कमज़ोर हो सकती है और सिलिकॉन वैली के अलावा भी, कई क्षेत्रों को नुकसान पहुँच सकता है। सप्ताहांत में हुई इस घोषणा ने अमेरिका की टैक्नॉलजी दुनिया में अफरा-तफरी मचा दी। विदेशी कर्मचारी देश से बाहर फँस जाने के डर से उड़ानों की तलाश में जुट गए, जबकि सिलिकॉन वैली की कंपनियों ने कर्मचारियों को यात्रा न करने की सलाह दी। कुछ घंटों में ही वाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी कि यह फीस सिर्फ नए वीज़ा आवेदनों पर लगेगी और वह भी एक बार की होगी।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

विचार बिन्दु

महान ध्येय का मौन में ही सृजन होता है। –साने गुरूजी

स्वास्थ्य सेवाओं में हर कहीं खामियां मिली सीएजी की जांच में

सभी लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था करना किसी भी कल्याणकारी शासन की प्रमुख जिम्मेवारी होती है। स्वास्थ्य राज्य के मूलभूत दायित्वों में शामिल है। नागरिकों के स्वस्थ रहने का अधिकार न केवल उनकी व्यक्तिगत भलाई से जुड़ा है बल्कि यह राष्ट्र की प्रगति, उत्पादकता और सामाजिक स्थिरता के लिए भी अनिवार्य है।लेकिन अब स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं जिस प्रकार बाज़ार के हवाले की जा रही हैं वह चिंताजनक है। हालांकि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जिस प्रकार स्वतंत्रता, समानता और न्याय को नागरिकों के मौलिक अधिकार बनाया उसी तरह स्वास्थ्य को संविधान में सीधे तौर पर मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे राज्य की जिम्मेदारी और नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में प्रमुखता दी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न व्याख्याओं से स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जरूर प्रतिष्ठित हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह व्याख्या की है कि 'जीवन का अधिकार' केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। गरिमापूर्ण जीवन का अर्थ है कि नागरिकों को न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण और सर्वसुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों। मगर यह अब राज्य के लिए खुद करना दुरूह होता जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 21(जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के साठ अनुच्छेद 39(इ) और 39(एफ)में राज्य को यह निर्देश देते हैं कि श्रमिकों और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिले। अनुच्छेद 42 में मातृत्व और प्रसूति संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी मानी गई है। अनुच्छेद 47 में स्पष्ट प्रावधान है है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए तथा जनस्वास्थ्य में सुधार करे।यानी संविधान ने स्वास्थ्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों में डालकर इसे राज्य का दायित्व तो बनाया, लेकिन न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं माना। आज व्यावहारिक स्थिति बताती है कि राज्य संविधान निर्देशित इस जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा पा रहा है। योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन अकर्मण्य कार्यपालिका उनका प्रभावी क्रियान्वयन करने में असफल रहती है। राज्य सरकार की इस असफलता की सच्चाई राज्य के वित्त प्रबंधन पर निगाह रखने वाली संवैधानिक संस्था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नई रिपोर्ट में भी खुल कर सामने आई है।

स्वास्थ्य मानव विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक और आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक आधारभूत घटक है। नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सीएजी की इस नमूना जांच में सामने आया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और पैरामेडिक्स की कमी है, सरकारी चिकित्सा संस्थानों के आईपीडी में सामान्य शल्य चिकित्सा, बाल रोग, अस्थि रोग और दुर्घटना एवं ट्रॉमा वार्ड जैसी आवश्यक न्यूनतम सुनिश्चित सेवाओं का भी अभावहै, वहां आपातकालीन, गहन चिकित्सा इकाइयों, रक्त बैंकों जैसी सेवाओं में भी कमियां हैं, सरकारी अस्पतालों और जिला औषधि गोदामों में आवश्यक दवाओं की पूरी उपलब्धता नहीं है, चिकित्सा इकाइयों को जारी की गई दवाइयां मांग की गई मात्रा से कम होती हैं, औषधि खरीद के लिए दर अनुबंधों को अंतिम रूप देने में अनावश्यक देरी होती है और क्रय आदेश तब दिए जाते हैं जब बफर स्टॉक निर्धारित बफर स्तर से बहुत नीचे चले जाते हैं, प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टें देरी से मिलती हैं, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के बिनाही स्थानीय स्तर पर दवाइयां खरीद ली जाती हैं, अमानक गुणवत्ता वाली दवाओं का निर्माण करने वाली फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई में काफी में शिथिलता होती है और सरकारी संस्थानों में में विभिन्न श्रेणियों में भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। लेखा परीक्षा में राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, बिजली और पीने योग्य पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान तक में कमियां पाई गईं। सीएजी की रिपोर्ट में यह चिंताजनक जानकारी भी सामने आई है कि राज्य के रेगिस्तानी, आदिवासी और मैदानी इलाकों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की कमी है और राज्य सरकार के पास इस कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए कमी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की कोई ठोस योजना नहीं है।

स्वास्थ्य मानव विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक और आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक आधारभूत घटक है। नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सीएजी की इस नमूना जांच में सामने आया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और पैरामेडिक्स की कमी है।

प्रशासन तंत्र की घोर निष्क्रियता को दर्शाती एक और बात लेखापरीक्षा में सामने आई है कि राज्य की चिकित्सा परिषद की न तो संरचना और न ही कार्यप्रणाली राजस्थान चिकित्सा अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसी प्रकार राज्य फार्मेसी परिषद ने भी प्रदेश में फार्मेसी निरीक्षकों की नियुक्ति ही नहीं की है। सवाल उठता है कि इन निकायों द्वारा प्रभावी नियमन सुनिश्चित करने के लिए राज्य चिकित्सा परिषद और राज्य फार्मेसी परिषद के कामकाज की निगरानी प्रशासनिक स्तर पर क्यों नहीं की जाती। भारी भरकम शीर्ष प्रशासनिक अमले के बावजूद इन खामियों के लिए कौन जिम्मेवार है यह सवाल निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं पूछते। वे सीएजी की रिपोर्टें शायद ही गौर से पढ़ते हों जो स,वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नियमित रूप से विधान सभा के पटल पर राखी जाती है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव इस चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। उनकी मदद करने के लिए निदेशक (जन स्वास्थ्य) है, जो समग्र योजना बनाने और गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएंडएचओ) और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ) योजनाओं के प्रशासन और कार्यान्वयन में मदद करते हैं। इसी प्रकार प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग (डीएमई) के प्रशासनिक प्रमुख हैं और आयुक्त (डीएमई) उनकी सहायता करते हैं, जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। कॉलेजों के प्रधानाचार्य और नियंत्रक (पी एंड सी) संस्थानों के प्रमुख हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध प्रत्येक अस्पताल एक अधीक्षक के प्रभार में कार्य करता है।सभी को मोटा वेतन और साथ में अनेक सुविधाएं मिलती हैं। मगर वे जो परिणाम देते हैं उसकी पोल सीएजी की उस रिपोर्ट में खुलती है मगर किसी का बाल भी बांका नहीं होता।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने 2025 तक समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। इसके अलावाराज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च को राज्य के बजट के 8 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाने की भी परिकल्पना की गई है। लेकिन हम पाते हैं कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय1.08 और 1.36 प्रतिशत के बीच ही रहा, जो दर्शाता है कि 2.5 प्रतिशत का लक्ष्य इस वर्ष तक प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय 8 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 5.25 और 6.95 प्रतिशत के बीच रहा है। सीएजी की रिपोर्ट यह चिंताजनक आंकड़ा भी देती है कि राज्य में स्वीकृत पदों की संख्या 22,018 के मुकाबले 15,121 चिकित्सक ही उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि राजस्थान सरकार के पास स्वास्थ्य क्षेत्र में भर्ती और स्टाफिंग के लिए कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) की तर्ज पर अपनी नीतियाँ बनाएं। लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने कोई राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य नीति नहीं बनाई है।

लेखापरीक्षा ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपलब्ध धन की निरंतर बचत और अपर्याप्त उपयोग भी पाया है, जो विभागों में अप्रभावी नियंत्रण का संकेत है। 2016-17 से 2021-22 तक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल बजट 77,246.20 करोड़ रुपयों में से, व्यय 71,188.81 करोड़ रुपये ही था। 2016-17 से 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पूंजीगत मद में 1,079.11 करोड़ रुपये (18.52 प्रतिशत) और राजस्व मद में 4,978.28 करोड़ रुपये (7 प्रतिशत) की कुल बचत हुई। अर्थात सरकार ने बजट में जितना धन रखा वह पूरा खर्च नहीं हुआ क्योंकि प्रशासनिक तंत्र अपनी जिम्मेवारी से लापरवाह रहा। संवैधानिक संस्था की यह रिपोर्ट बताती है कि शासन का काम जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय प्रश्न है। यह क्योंकि राज्यों का विषय है इसलिये इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार पर अधिक होती है जो राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सीएजी की रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखी जाती है और अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचित प्रतिनिधि इसे पढ़ कर उसमें बताई गई खामियों को ठीक करने के लिए आवाज़ उठा कर सरकार को सक्रिय कदम उठाने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन अनुभव बताता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास उन्मादी राजनीति करने के अलावा और किसी में रुचि नहीं होती है। आमजन से जुड़े स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में खम ठोंकने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि कभी गंभीर विमर्श नहीं करते। भारत विश्व शक्ति बनने का सपना देख रहा है। यह सपना तभी साकार हो सकता है जब उसका नागरिक स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित महसूस करे। सार्वजनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं मीडिया प्रचार में नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन में दिखनी चाहिए।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

बांसवाड़ा में उगेगा सोने का सूरज

शारदीय नवरात्रि की पावन बेला में विकास का महाशिलान्यास करेंगे पीएम मोदी

शक्ति और साधना के प्रतीक शारदीय नवरात्रि की पावन बेला में राजस्थान का जनजाति बहुल दक्षिणांचल नई ऊर्जा और नए विश्वास का साक्षी बनने जा रहा है। देवी त्रिपुरा सुंदरी की दिव्य छत्रछाया, माही माता की जीवनदायिनी धारा, मानगढ़ के गौरवशाली इतिहास और संत मावजी की पवित्र भूमि पर 25 सितंबर का दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि भविष्य के उज्ज्वल अध्याय की शुरुआत बनकर दर्ज होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति के नापला गांव पहुंचकर 1 लाख 22 हजार 441 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जनजाति बहुल दक्षिणांचल वागड़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हो रहा यह आयोजन एकात्म मानववाद और अंत्योदय के आदर्शों को नई ऊर्जा देगा, मानो देवी की आराधना और विकास का संकल्प एक साथ साकार हो रहे हों।

राजस्थान सरकार का दूरदर्शी सहयोग :-प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा को सफल बनाने में राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुख्यमंत्री ने स्वयं नापला गांव और आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों का गहन निरीक्षण किया। मंच निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सहायता, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण से लेकर हर व्यवस्था को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियां और बुनियादी ढांचे के विकास में त्वरित कार्रवाई कर केंद्र की योजनाओं को गति दी। मुख्यमंत्री ने इसे केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि दक्षिण राजस्थान के जनजातीय अंचल को आत्मनिर्भर बनाने का युगांतकारी कदम बताया है।

प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर प्रदेश की दूसरी और देश की महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा परियोजना माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। लगभग 42,000 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना 2800 मेगावाट की क्षमता वाली होगी, जिसमें 700-700 मेगावाट की चार अत्याधुनिक इकाइयां शामिल हैं। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन तहसील के आड़ीभीत, बारी, कटुम्बी, सजवानिया और रेल गांवों में बनने वाली यह परियोजना प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित होगी, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बिना स्वच्छ बिजली उत्पादन में सक्षम है। यह परियोजना केवल बिजली का स्त्रोत नहीं, बल्कि प्रकृति और प्रगति के बीच सामंजस्य का प्रतीक होगी।

ये कार्यक्रम भी हैं प्रस्तावित :-निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बांसवाड़ा से 1 लाख 22 हजार 670 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान को 42 हजार करोड़ रुपए की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं और विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे इस अवसर पर राजस्थान सरकार के 30 हजार 339 करोड़ रुपए से अधिक के 48 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे। इस मौके पर 15 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के अंत में पीएम कुसुम योजना के विभिन्न लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे।

जनजाति अंचल के सपनों को लगेंगे पंख :-इस परियोजना से बांसवाड़ा को दुनिया के परमाणु ऊर्जा मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। इस परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर खुलेंगे और आसपास के व्यवसायों को नई दिशा मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और दक्षिण राजस्थान का जनजातीय अंचल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। यह केवल रोजगार की गिनती नहीं, बल्कि उन सपनों का उत्सव है, जो पीढ़ियों से अवसर की राह देख रहे थे। राजस्थान सरकार ने परियोजना से जुड़े स्थानीय रोजगार प्रोत्साहन, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र और औद्योगिक इकाइयों के विस्तार की योजनाएं भी तैयार की हैं, ताकि बांसवाड़ा के युवाओं को सीधा लाभ मिल सके।

भव्य आयोजन, अप्रतिम उत्साह :-माहीबांध बैकवॉटर की मनमोहक प्राकृतिक छटा के बीच नापला गांव का आयोजन स्थल विकास और आस्था के महाकुंभ में बदल चुका है। प्रधानमंत्री के मंच, वीवीआईपी गैलरी और जनसभा के लिए विशाल डोम और विशेष पंडाल बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियां और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीमें मुस्तैद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं बार-बार स्थल का दौरा कर अंतिम तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। शहर और आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रशासन द्वारा आमजन की सुविधा के लिए शटल बस सेवा, पेयजल स्टॉल, चिकित्सा केंद्र और पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। पूरे क्षेत्र में ऐसा उत्साह है मानो यह केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि पूरे जनजातीय अंचल का अपना पर्व हो।

श्रद्धा, संस्कृति और विकास का अद्भुत संगम :-त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति, माही माता की पावन धारा और संत मावजी के तपोभूमि की आभा में यह शिलान्यास केवल ऊर्जा परियोजना का आरंभ नहीं, बल्कि विकास और संस्कृति के अद्वितीय संगम का साक्ष्य है। नवरात्रि की आराधना जहां शक्ति और संरक्षण का संदेश देती है, वहीं यह परियोजना हरित ऊर्जा और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर को राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने वाला ऐतिहासिक पर्व बताते हुए इसे राज्य के उज्ज्वल भविष्य का संकल्प माना है।

भविष्य के उजाले का व्रत :-प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल परियोजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि दक्षिण राजस्थान के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का व्रत है। यह संदेश है कि जब श्रद्धा, संकल्प और राज्य-केंद्र की साझी प्रतिबद्धता साथ चलें, तो विकास का हर मार्ग सुगम हो जाता है। माही बांध की लहरों पर गूंजती ऊर्जा क्रांति की यह गाथा राजस्थान को वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर स्थापित करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया सूरज लेकर आएगी। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि शक्ति की उपासना और विकास का संकल्प जब एक साथ फलीभूत होते हैं, तब इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अध्याय अंकित होते हैं।

डॉ. कमलेश शर्मा
अतिरिक्त निदेशक,
जनसंपर्क पुलिस मुख्यालय,
जयपुर

चुनाव आयोग, नेता प्रतिपक्ष व विपक्षी दल तथा सत्ताधारी दल का अनिर्णीत दंगल

महावीर सिंह

अपने देश में शासन व्यवस्था के लिए कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। अपेक्षा यह होती है कि कानून संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप और संवैधानिक प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना करके बने।

कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है, इसकी जांच परख करने का,कानून की व्याख्या करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। यदि कभी ऐसा लगता है कि जो कानून बना है उस में कोई ऐसी कड़ी ओर जुड़नी चाहिए जो कानून को पूर्णता प्रदान करे, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है।

सामान्यत: आम जनता यह मानकर चलती है कि संसद द्वारा जनहित में ही कानून बनाया है। किंतु कई बार कानून बनाते समय ही या बाद में, सरकार के क्रियाकलापों को देख कर जनता सशंकित हो जाती है कि बनाए गए कानून का बेजा दुरुपयोग भी किया जा सकता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि संविधान सभा में हुई बहस का सार यह है कि संसद राज्य विधान सभाओं के लिए चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों, कोई शक की गुंजाइश न हो और उसके लिए निष्पक्ष चुनाव आयोग हो। निष्पक्षता से काम के सकने वाले चुनाव आयोग के गठन के लिए, ईमानदार, निष्ठावान, निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद कानून बनाए । जब तक यह कार्य पूर्ण न हो तब की अवधि के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाली कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नाम तय करे।

किंतु जब संसद में कानून बनाया तो उसमें प्रधान मंत्री, उनके द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री व नेता प्रतिपक्ष को चयन करने वाली कमेटी में रखा। इसका सीधा सा अर्थ है कि जैसा केंद्र सरकार चाहेगी, वैसा ही चुनाव आयोग बनेगा। निष्पक्ष हो भी सकता है अथवा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सत्ता पक्ष की इच्छानुसार भी ले सकता है।

अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस चयन समिति में रखा जाता तो देश पर क्या खतरा आ जाता? चलिए मान लेते है,कानून बनाना संसद का अधिकार है और भारत का संविधान में न्यायपालिका व संसद के अधिकार क्षेत्र अलग अलग तय किए हुए है।इसलिए,सामान्यत तर्क यह दिया गया कि संसद व कार्यपालिका के काम में न्याय पालिका का दखल क्यों हो?? तो फिर, कम से कम ऐसा कानून तो बनाते जिसमें जाहिराना तोर पर तो यह नहीं लगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही बनेगा जिसे सरकार चाहेगी व अर्थात सरकार का मर्जी दान। यह ठप्पा लगा चुनाव आयुक्त बनेंगे, तो, चाहे वह पूर्णत: निष्पक्ष, सक्षम, ईमानदार ही क्यों न हो, उसके कार्यों पर शंका करने की गुंजाइश हमेशा रहेगी।

2023 में संसद में कानून बनाया "मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त (---) अधिनियम"। कानून में प्रावधान किया की भारत की कोई भी अदालत चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी आधिकारिक कार्य, निर्णय, बयान आदि को लेकर, सिविल या अपराध के लिए उनके जीवनकाल में मामला नहीं ले सकती। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारीश से ही हटाया जा सकता है।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल एक विहित प्रक्रिया द्वारा संसद ही हटा सकती है, वैसे ही जैसे किसी उच्च या उच्चतम बी न्यायालय के न्यायाधीश को तो फिर इस प्रकार के कानून की कहां आवश्यकता थी? मुझे स्मरण नहीं पडता कि कभी किसी चुनाव आयुक्त पर चुनाव से संबंधित किसी कार्य के लिए कोई अपराधिक या सिविल मुकदमा चला हो। 2023 से पहले 70 साल में ऐसा कानून बनाकर, इतना प्रोटेक्शन देने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई??

क्या पहले से अंदेशा था कि जानबूझ कर गलत मतदाता सूचियों के जरिए वोट इधर उधर करने,चुनावी धांधली के मामले उठेंगे और सरकार की मर्जी से नियुक्त चुनाव आयुक्तों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हो सकते है?? मान लिया, द्वेषता के कारण कोई ऐसा कर सकता है तो यह प्रोटेक्शन चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल तक दिया जाना उचित हो सकता है किंतु यदि इस बात के प्रथम दृष्टया सबूत हों कि किसी चुनाव आयुक्त के निर्देशों पर कोई गलत निर्णय किया गया तो कार्यकाल समाप्ति के बाद मुकदमा क्यों नहीं चले?? लोक सभा में नेता प्रति पक्ष व कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने ऐसे आरोप लगाए है कि मतदाता सूचियों में मनमर्जी से नाम हटाए और जोड़े गए है और अब भी ऐसा किया जा रहा है।

आयोग का कहना है ऐसा किया ही नहीं जा सकता।अभी कर्नाटक की एक विधान सभा आलंद के संबंध में प्रेस के समक्ष एक प्रजेंटेशन में नेता प्रति पक्ष में कहा है कि ऐसा किया गया है। जो कुछ कहा गया उसका सार यह है ----- कि पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट में से कुछ नामों को हटाने की एप्लिकेशन भर के ऑनलाइन, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सब मिट की जाती है। एप्लिकेशन सबमिट करने में कुछ मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया गया। उस मोबाइल फोन पर प्रार्थनापत्र सत्यापन के लिए मेसेज जाता है और फिर उस वोटर का नाम हटाया जाता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इस गड़बड़ी का भंडा फूटने पर कर्नाटक चुनाव आयुक्त ने जांच पड़ताल करवाई और पाया कि इस प्रकार के 6 हजार से ऊपर नाम कटवाने के प्रार्थना पत्र दाखिल हुए। जांच में 24 सही पाए गए और बाकी, वास्तव में संबंधित वोटर्स की जानकारी के बिना दाखिल किए गए। कर्नाटक सरकार की पुलिस की CID शाखा में एक एफआईआर दर्ज कराई जिसकी जांच चल रही है।

आरोप यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय से जांच में वांछित सूचनाएं --- ई मेल जिस मेल आईडी से की गई उसका IP एड्स दिया जाए, जिन मोबाइल नंबरों का हवाला प्रार्थना पत्रों में दिया वह मोबाइल नंबर नहीं दिया जा रहे। प्रार्थना पत्र के सत्यापन के लिए जिस मोबाइल नंबर पर मेसेज भेजे वह नंबर तथा ओटीपी भेजे गए होंगे उनका पूरा विवरण अर्थात OTP ट्रेल आदि का पूरा विवरण दिया जाए। चुनाव आयोग के प्रेस नोट दिनांक 19 सितंबर 25 के द्वारा बताया गया है कि CID द्वारा चाही जा रही। समस्त जानकारियां दे दी गई है। वहां जांच में देरी हो रही है।

चुनाव आयोग द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा संभव नहीं क्यों कि ऑनलाइन किसी मतदाता का नाम हटाया ही नहीं जा सकता।

अभी तक, सार्वजनिक रूप से जो सामग्री सामने आई है, जो विचार विभिन्न लोगों के सामने आए है उनका सार यह है कि--ऑनलाइन नाम हटवाने का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। यह सब एक संगठित गिरोह भी कही दूर बैठ कर सकता है अर्थात आयोग की वेबसाइट में घुसकर नाम हटवाने का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। अब सत्यापन के लिए कि आवेदन सही है उसके लिए जिस मोबाइल नंबर का हवाला नाम हटवाने के प्रार्थना पत्र में दिया है उस पर मेसेज व ओटीपी जाएगा। का उपयोग कर यह कनफर्म किया जाएगा कि हां, प्रार्थनापत्र दिया गया है अर्थात एक ओर ईमेल आयोग की वेबसाइट पर गया।

आरोप यह है कि यह सारी कार्यवाही दूरस्थ किसी काल सेंटर से की गई है जिसका संबंधित वोटर को पता ही नहीं अर्थात कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम को हटवाने के लिए इतनी कार्यवाही तो कर ही सकता है।

इसके पश्चात आता है BLO द्वारा सत्यापन तो जिस प्रकार आवेदन फर्जी तरीके से किया जा सकता है, उसी प्रकार, सत्यापन से संबंधित कार्यवाही बिना वास्तविक मतदाता की जानकारी के क्यों नहीं की जा सकती??? जिस कल सेंटर से आवेदन की कार्यवाही हुई, उस से या दूसरे कल सेंटर से BLO के फर्जी हस्ताक्षरों से सत्यापन रिपोट्र्स अपलोड कर दीजिए। सारी प्रक्रिया से सही वोटर व सही BLO को कुछ पता ही नहीं चलेगा।

आयोग से पूछा जा रहा है कि इस फर्जी प्रक्रिया में जिस जिस सोर्स से मेल आयोग की वेब साइट पर अपलोड हुए और जहां जहां आयोग से मेल गए उन के ओरिजिन व डेस्टिनेशन के एड्रेस व जहां जहां आयोग से ध्ऊइ गए उनकी पूरी ट्रेल जांच अधिकारी को दी जाए ताकि यह साफ हो की यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसके सोर्स कहां है। नं. ---- आयोग की ओर से पैरवी कर्ताओं का कहना है कि सारी समारी कर्नाटक सरकार की CID को दे दी। इसके विपरीत जांच करने वालों व आरोप लगाने वालों का कहना है जांच में आवश्यक पूरी जानकारी तथा फर्जी आवेदन करने वालों व आगे की कार्यवाहियों के स्त्रोतो का पता चले ऐसी जानकारी नहीं दी गई है?

चलिए,यह तो आरोप प्रत्यारोप हुए किंतु क्या आयोग को इसकी त्वरित निष्पक्ष जांच नहीं करनी चाहिए कि उस की वेबसाइट में अवैध तरीके से घुश के इस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है क्या और यदि की गई है तो क्या उचित समाधान नहीं करना चाहिए और जनता को नहीं बताना चाहिए??

क्या जन हित में, इस सारी फर्जी कार्यवाही का पता चलते ही,स्वयं केंदीय चुनाव आयोग द्वारा केंद्र सरकार से किसी सक्षम केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाने का अनुरोध करना ज्यादा उचित नहीं होता? चुनाव आयोग को जनता को बताना चाहिए कि चुनाव आयोग में सिर्फ एक दर्ज करवाने के ओर क्या क्या प्रयास ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए किए।

अब एक दो प्रश्न पाठकों के लिए ::-- मतदाता सूचियां बनाता है चुनाव आयोग, आरोप लगाए जा रहे है आयोग पर तो फिर कुछ असंबद्ध लोग या राजनीतिक पार्टियां मिनटों में ही आयोग का बचाव करने क्यों आ जाते है,मानों की उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम हो। क्या आयोग कोई असहाय नाबालिग बालक जो बाहरी चौधरियों से सहायता का मोहताज है?

बिहार की मतदाता सूचियों के SIR के संबंध में आयोग में सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से अपना बचाव किया तो सामान्य व्यक्ति प्रथम दृष्टया यह नहीं सोचेगा कि कहीं कुछ झोल है क्या??

अगर देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां कोई बात कहती है तो तसल्ली से उनकी बात पर गौर करके उन्हें अपना पक्ष रखने के बजाए आयोग अपने बचाव व आरोप लगाने वालों पर आक्रामक मुद्रा में क्यों आ जाता है?

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

राशिफल

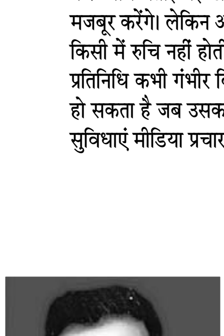

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 24 सितम्बर, 2025

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, चित्रा नक्षत्र सायं 4:17 तक, ऐन्द्रयन योग रात्रि 9:02 तक, तैतिल करण सायं 5:59 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-तुला, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरू-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज राजयोग सायं 4:17 तक है। रवि योग सायं 4:17 से आरम्भ होगा। आज से रवि-उलसानि मु. मास 4 आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:14 तक, शुभ 10:49 से 12:19 तक, चर 3:19 से 4:58 तक, लाभ 4:58 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:20, सूर्यास्त 6:19

मेष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

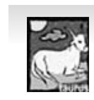

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

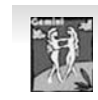

मिथुन
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।

कर्क
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

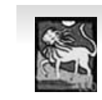

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

तुला
यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में चल रहे मतभेद दूर होने लगेंगे।

वृश्चिक
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

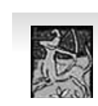

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

मकर
व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

कोटा

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

कोटा, बुधवार 24 सितम्बर, 2025

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर

2800 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना सहित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सेवा ही संकल्प,
राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा... 75 वर्ष

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

विकास पथ पर
आपणो अग्रणी राजस्थान...

1 लाख 8 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात

15 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण

जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर से नई ट्रेनों की शुरुआत

मुख्य अतिथि

नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

25 सितम्बर, 2025 I दोपहर 12:00 बजे | स्थान : नापला, छोटी सरवन (बांसवाड़ा)

आप सादर आमंत्रित हैं

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान संवाद

एफ.आई.आर. पर एफ.आर. एफ.आर. फिर एफ.आर., आखिर माजरा क्या है ?

निति अनुसार एक अपराधिक मामले की जांच के लिए तीन बार जांच अधिकारी बदला जा सकता है। परन्तु, नवीन चौधरी की एफ.आई.आर की जांच में आखिर कब तक जांच अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे ?

-कार्यालय संवाददाता-

- **नवीन चौधरी की एफ.आई आर सीकर रोड़ पर बनी गिरधर कॉलोनी के प्लॉट नम्बर विवाद से सम्बन्धीत है।**
- **हैरानी की बात है कि जेडीए के आदेश अनुसार स्वयं नवीन चौधर ही उक्त जमीन के कब्जा धारी है और रिहायशी जमीन पर अवैध तरीके से शादी का हॉल और भोजनालय चला रहे है।**

जयपुर। सीकर रोड, गिरधर कॉलोनी के निवासी, नवीन चौधरी, द्वारा एक जमीन के विवाद पर 13 जुलाई 2023 को मुरलीपुरा थाना, जयपुर, में कराई गई एफ.आई.आर. का मामला, किसी भी अन्य जमीनी विवाद में संबंधित एफ.आई.आर. से ज्यादा रोचक साबित हो रहा है। नवीन चौधरी की एफ.आई.आर. संख्या 365 पब्लिक 2023 का मामला रोचक इसलिए है कि इस मामले में पिछले ढाई वर्ष से तीन जांच अधिकारियों ने रिपोर्ट पेश करी है, जिसमें से पहले जांच अधिकारी का रिपोर्ट में स्पष्ट कहना था, कि दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में मामले को केवल सिविल स्वरूप का बताया गया और मामले पर एफ.आर. लगा दी गई। इसके बाद एक अन्य जांच अधिकारी ने इस मामले में आपराधिक मामला होने व उसकी जांच होने की पुष्टि करें, परंतु जांच अधिकारी का तबादला हुआ और मामले की जांच पर एफ.आर. लगा दी गई। तत्पश्चात एक तीसरी जांच अधिकारी ने इस मामले की जांच करी और इसे सिविल स्वरूप का बताया और किसी आपराधिक तत्व नहीं पाए जाने के कारण मामलें में पुनह एफ.आर. लगाई।

गौर फरमाने योग्य है कि इस मामलें में तीन बार एफ.आर. लगने के बाद शिकायतकर्ता नवीन चौधरी ने पुलिस प्रशासन की दया दृष्टि पाते हुए इस एफ.आई.आर. की जांच के लिए चौथी बार एक जांच अधिकारी की नियुक्ति कराए जाने और एफ.आर. हटाने में सफलता प्राप्त की।

परंतु सवाल यह है कि एक मामले की जांच कितने जांच अधिकारी कर सकते हैं और क्या तीन बार एफ.आर. लगने के बाद भी पुलिस प्रशासन मामले को पुन खोलने और जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के गृह विभाग में 1 जनवरी 2019 को एक नीति जारी करी थी, इस नीति में स्पष्ट लिखा है, कि "एक प्रकरण में किसी भी परिस्थिति में समस्त अधिकारियों द्वारा अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन कुल मिलाकर तीन बार से अधिक नहीं किया जा सकेगा।" इस नीति में आगे लिखा है कि "उक्त तीन अनुसंधान अधिकारियों की गणना में प्रथम अनुसंधान अधिकारी की भी गणना की जाएगी।"

राज्य सरकार द्वारा इस नीति का गठन किया जाना तर्कसंगत और लाज़मी इसलिए भी लगता है कि एक एफ.आई.आर. की जांच अनंत समय और अनगिनत जांच अधिकारियों द्वारा नहीं की जा सकती है, परंतु नवीन चौधरी की एफ.आई.आर. के मामले में इस स्पष्ट नीति का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है।

क्या शिकायतकर्ता की मनमर्जी की रिपोर्ट ही इस फिर की जांच को पूर्ण कर सकती है? क्योंकि तीन बार इस मामले में जांच के बाद फर लग चुकी है और एफ.आर. में दर्ज आरोप सिद्ध करने के लिए तथ्य उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इस मामले का सबसे रोचक तथ्य यह है, कि जिस जमीन पर चल रहे विवाद को लेकर यह एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

वह जमीन सीकर रोड, पर गिरधर कॉलोनी का प्लॉट नंबर चार है और इस रिहाई सी प्लॉट पर स्वयं जेडीए ने जांच कर पाया है, कि नवीन चौधरी ही बिना अनुमति एवं स्वीकृति के करीब 2300 वर्ग गज में एक चार बाग के नाम से रेस्टोरेंट में बैंक्वेट हॉल का अवैध निर्माण कर व्यावसायिक संचालन कर रहे हैं। जीडीए ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि, यह निर्माण बिल्डिंग बाय लॉज का उल्लंघन होने के अलावा अवैध में अनाधिकृत है और इस प्लॉट पर स्वयं नवीन चौधरी का ही कब्जा हैं।

दरअसल इस जमीन को नवीन चौधरी ने श्रीनाथ कृपा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर रिहायशी कॉम्पलेक्स बनाने का अनुबंध किया था, इस अनुबंध के अनुसार डेवलपर द्वारा रिहायशी कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु रकम मुहैया कराई जा रही थी और जमीन देने के आवाज में नवीन चौधरी को रिहायशी परिसर में फ्लैट मिल रहे थे। दोनों डेवलपर और नवीन चौधरी ने मिलकर एक कंपनी का भी गठन किया था, जो निर्माण कार्य को पूर्ण करती।

परंतु नवीन चौधरी द्वारा ही जमीन का कब्जा नहीं कंपनी को नहीं दिया गया और पुलिस प्रशासन की मदद से इस मामले में वर्ष 2023 में एफ.आई.आर. दर्ज कराई। जिसमें तीन बार एफ.आर. लगने के बाद भी पुन जांच अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है।

छात्रों से मारपीट करने वाले छह जने गिरफ्तार

जयपुर। शिप्रापथ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैगोर कॉलेज के छात्रों से मारपीट करने वाले हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं एक नाबालिग को बाल सुधार को निरूद्ध कर गृह भेजा गया है। बदमाशों ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इसके बाद पांचों युवकों की इंस्टाग्राम आईडी और मोबाइल नंबर ट्रेस कर पहचान के बाद पकड़ा।

शिप्रापथ थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि शिप्रापथ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैगोर कॉलेज के छात्रों से मारपीट करने वाले हेमंत मीणा निवासी अलवर,सुमित शर्मा निवासी अलवर मनीष कुमार मीणा निवासी अलवर,सौरभ मीणा उर्फ गोलू मीणा निवासी दौसा और जयशिव सैनी निवासी दौसा को गिरफ्तार किया गया है और एक एक बाल अपचारी निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं पांचों जयपुर में पीजी में कमरा लेकर रहते।

मारपीट की घटना 20 सितंबर की थी। टैगोर कॉलेज में पढ़ने वाले भावेंद्र कुमार (22) निवासी बाड़मेर ने मामला दर्ज करवाया था कि वह अपने दोस्त विनोद के साथ बाइक पर अपने कमरे से जा रहा था। टैगोर स्कूल के सामने 4-5 लोगों ने बाइक रुकवाकर अचानक से लाठी और सरिया से मारपीट करना शुरू कर दिया।

आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी के सामने पति की चाकू से गोद कर हत्या करने वाले एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि करधनी थाना इलाके में सरना डूंगर रीको एरिया (मेटल फैक्ट्री) में काम करने वाले रवि कुमार की बीस सितंबर को दो मजदुरो ने चाकू घोंपकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुसि ने हरिशंकर कुशवाह(20) निवासी कुलपाडा जिला महुबा (यूपी) हाल करधनी को गिरफ्तार किया गया हैं और वहीं एक अन्य आरोपित आशीष निवासी कुलपाडा जिला महुबा (यूपी) की तलाश की जा रही है इस मामले रवि कुमार की पत्नी निर्मला ने पति की हत्या का मामला दर्ज करवाया था कि वह रवि निवासी गांव कानसिंहपुरा जिला झुंझुनूं के साथ छह साल से लिव इन में रह रही हैं। तीन साल से रवि मेटल कंपनी में काम कर रहे था।

डाक विभाग भर्ती में फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने वाले गिरफ्तार

फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

जयपुर। भारतीय डाक विभाग में नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। जहां अलवर पुलिस ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) के पद पर फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तब की गई जब डाक विभाग की आंतरिक जांच में इन दस्तावेजों के फर्जी होने का पता चला। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि साल 2022 में हुई भर्ती प्रक्रिया में 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। नियुक्ति के बाद जब डाक विभाग ने सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जाँच करवाई तो हितेश कुमार, साहिल, मनीषा नैना, शैलेन्द्र कुमार और पिंटू कुमार जैसे कुछ लोगों ने तमिलनाडु के चेन्नई बोर्ड की जाली मार्कशीट जमा करने का पता चला।

इस मामले में पहले हितेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस ने शैलेन्द्र कुमार निवासी मुड़िया खेड़ा, खैरथल-तिजारा को भी गिरफ्तार किया है, जिसने बताया कि उसने यह फर्जी मार्कशीट अपने दोस्त संदीप यादव के माध्यम से प्राप्त की थी। संदीप यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप ने स्वीकार किया कि उसने एक कोचिंग सेंटर के संचालक से अपने और शैलेन्द्र के लिए फर्जी अंकतालिकाएं बनवाई थीं।

उपमुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ देखी मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री

ायपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अउपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कच्ची बस्ती के बच्चों के साथ देखी मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री ाज कच्ची बस्ती के बच्चो के साथ आत्मीय भाव के साथ मुलाक़ात की। दिया कुमारी को अपने पास देखकर कच्ची बस्ती के बच्चो के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ट्राइटन माल में बच्ची के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी देखी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन पर बनी डॉक्यूमेंट्री में संदेश दिया की अगर हम अपने जीवन को दूसरी की ख़ुशी के लिए समर्पित करते है तो उसका कितना अच्छा परिणाम निकल कर आता है। बच्चो ने भी डॉक्यूमेंट्री देखकर इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन से जुड़ी यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ़ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत है। इसमें जो संदेश दिया गया है-दूसरों की खुशी के लिए काम करना ही सबसे बड़ा सुख है-उसे हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और प्रदेश के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं।और हम सबको भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए।

स्वास्थ्य शिविरों में 37 लाख से अधिक लोगों को मिला लाभ

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देशभर में चलाए जा रहे स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान से लाखों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियान प्रतिबद्धता के साथ संचालित कर आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से प्रदेश में अब तक 37 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि आमजन को अपने नजदीकी स्थान पर सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने एवं विभिन्न रोगों की स्क्रीनिंग कर उपचार एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियान का आयोजन किया गया है। इसके तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है, ताकि हमारी माताएं-बहनें स्वस्थ रहें और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। राजस्थान इस अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासनर सचिव राठौड़ ने बताया कि अभियान के तहत राजस्थान बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

फूड सेफ्टी टीम ने किया 884 लीटर नकली घी सीज

जयपुर । आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को सीएमएचओ जयपुर प्रथम की फूड सेफ्टी टीम ने चांदपोल बाज़ार स्थित अग्रवाल रोड लाइंस पर कार्यवाही कर 884 लीटर नकली घी सरस, कृष्णा, लोटस, गोरस ब्रांड सीज किया। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि इस फर्म का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि पैकिंग पर संदेह होने पर समस्त स्टॉक चेक करने पर सरस, लोटस,कृष्णा,गोरस के प्रतिनिधियों को मौके पर बुलाया गया। जिसमे सरस, कृष्णा, लोटस और गोरस घी के प्रतिनिधियों ने मौके पर उपस्थित हुए और अपने घी उत्पादों को मौके पर नकली होना बताया। टीम ने मौके से उक्त सभी घी कंपनियों के छह नमूने घी के लिए और मिलावट के संदेह में 884 लीटर घी सीज किया। ज्ञात हुआ कि यह घी नावा, कुचामन, परबतसर, मकराना और अन्य स्थानों पर बिकवाली के लिए जाता था नमूनों की लैब रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार सख्त अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र सिंह, पवन गुप्ता एवं विशाल मित्तल शामिल रहे। मौके पर अग्रवाल रोड लाइंस के मालिक अरुण कुमार जैन ने उक्त माल कहां से किस पार्टी द्वारा आगे भिजवाया जाना है की जानकारी नहीं होने बाबत अवगत करवाया।

'निशुल्क यूनिफॉर्म योजना में ओ.बी.सी. व ई.डब्लू.एस. छात्राओं को पुनः शामिल करे'

जयपुर। आल इंडिया ओ बी सी कांग्रेस नेता एवं स्टेट ओ बी सी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य राजेन्द्र सेन ने राजस्थान सरकार द्वारा पहली से 8वीं तक के सामान्य-ओबीसी के 15 लाख छात्र और 9 से 12वीं तक की 12 लाख छात्राएं को निशुल्क यूनिफार्म योजना से बाहर करने का विरोध करते हुए सरकार को चेताया है कि गरीब और ओ बी सी समाजो की छात्राओं को निधुल्क यूनिफार्म योजना के तहत निशुल्क यूनिफार्म देना जारी रखे वरना आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में इन छात्राओं के द्वारा घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी विरोध दर्ज कराया जायेगा

सेन ने बताया कि शिक्षा विभाग विद्यार्थियों से जुड़ी योजनाओं में लगातार कटौती कर रहा है।

मेजर दलपत सिंह के बलिदान दिवस पर उपमुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी

जयपुर । राजस्थान की वीर भूमि के अमर सपूत हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह के बलिदान दिवस पर विद्याधर नगर स्थित रावना राजपूत भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर मेजर दलपत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा,"मेजर दलपत सिंह का बलिदान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान प्रेरणा है। उन्होंने इजराइल के हाइफा शहर को आजादी दिलाकर भारत ही नहीं, बल्कि राजस्थान का नाम भी वैश्विक मानचित्र पर गौरवान्वित किया है।" उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार शहीदों और महापुरुषों के सम्मान में कई योजनाएं चला रही है। इन प्रयासों से नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना और इतिहास के प्रति सम्मान लगातार बढ़ रहा है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह स्मृति शिक्षण संस्थान का भी अनावरण किया। यह संस्थान आने वाली पीढ़ियों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास से भी जोड़ेगा। कार्यक्रम में महिलाओं ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत51 किलो की फूलों की मालापहनाकर किया। यह सम्मान समाज की ओर से उनके योगदान और प्रयासों के लिए था।दिया कुमारी ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने महिलाओं, बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।कार्यक्रम में संयोजकरणजीत सिंह,मोहन सिंह हाथोज,गुमान सिंह जोधा,गिरवर सिंह शेखावत,श्याम सिंह चोहान,महिपाल सिंहसहित समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अग्रसेन जयंती शोभायात्रा में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की शिरकत:- अग्रसेन जयंती के अवसर पर मंगलवार को सीकर रोड पर भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाग लिया। उन्होंने पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के पुरुषों और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि अग्रवाल समाज सदैव सेवा कार्यों और धार्मिक आयोजनों में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा, चाहे सेवा भवनों का निर्माण हो या शोभायात्राएं, समाज ने हमेशा एकजुटता और सौहार्द का परिचय दिया है।उपमुख्यमंत्री ने भगवान महाराजा अग्रसेन जी को समाजवाद और संतुलित व्यवस्था का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक हैं।इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी में रियायतों का उल्लेख करते हुए कहा, इस फेस्टिवल सीजन में जीएसटी को सरल और जनउपयोगी बनाया गया है, जिससे व्यापारियों पर करों का बोझ कम होगा और आम जनता को भी वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी।

नौकरी दिलाने के बहाने विवाहिता से दुष्कर्म

जयपुर। बगरू थाना इलाके में नौकरी दिलाने के बहाने होटल में बुलाकर एक विवाहिता से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार भांकरोटा की रहने वाली 35 वर्षीय विवाहिता ने मामला दर्ज करवाया है कि कुछ समय पहले आरोपित युवक से उसकी मुलाकात हुई थी। होटल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मिलने का दबाव डाला। 21 सितंबर को बगरू इलाके में स्थित एक होटल में नौकरी दिलाने के बहाने मिलने बुला कर दुष्कर्म किया। होटल से जाते समय किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पडताल में जुटी है वहीं श्याम नगर थाना इलाके में 19 वर्षीय एक लड़की से दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपित रिश्तेदार मिलने के बहाने घर आया था। पुलिस ने मामला दर्ज जांच में जुटी है।

मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे : हाईकोर्ट

- **अदालत ने शिक्षण संस्थाओं में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने को लेकर भी जानकारी पेश करने को कहा है**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार सहित यूजीसी से पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षण संस्थाओं में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने को लेकर भी जानकारी पेश करने को कहा है। अदालत ने मामले में शिक्षा मंत्रालय, प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और यूजीसी सहित सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है।

जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश सुजीत स्वामी व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अमित दाधीच ने अदालत को बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के अनुसार साल 2015 से 2023 तक कोटा, बारां और झालावाड में 12 से तीस साल के 1799 लोगों ने आत्महत्या की। वहीं 2021 से गत मार्च माह तक दस से तीस साल की उम्र के सीकर में 464, जयपुर दक्षिण में 172 और जोधपुर पूर्व में 187 सहित अन्य जगहों में दर्जनों लोगों ने आत्महत्या की है।

इसके अलावा एनसीआरबी की साल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में सात फीसदी से अधिक आत्महत्या छात्रों से संबंधित है। वहीं 2 फीसदी से अधिक किशोर अपराध दर भावनात्मक तनाव से जुडी है। याचिका में कहा गया कि शैक्षिणक संस्थानों में न तो मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र बने हैं और ना ही मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है।

इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में भी शामिल नहीं किया गया है। जबकि यदि शैक्षिणक संस्थानों में ही विद्यार्थियों को मानसिक दबाव से निपटने के लिए तैयार किया जाए तो आत्महत्याओं पर काफी हद तक कमी लाई जा सकती है।

याचिका में गुहार की गई है कि सभी शैक्षिणक संस्थानों में अगले छह माह में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाए। वहीं आयु और कक्षा अनुसार मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम भी लागू किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है।

गहलोत महसूस कर रहे है राजनीतिक असुरक्षा, भूल गए विपक्ष का धर्म : सतीश पूनिया

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत के बयान पर तिखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गहलोत राजनीतिक असुरक्षा महसूस कर रहे है और विपक्ष की भूमिका सही तौर पर नहीं निभा पा रहे। सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए

- **गहलोत सहन नहीं कर पा रहे सामान्य परिवार के व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर समझते है फंडामेंटल राइट्स : सतीश पूनिया**

इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे है। विपक्ष में रहने के बावजूद गहलोत एक आंदोलन तक नहीं कर पाएं, अगर उनको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कॉचिंग की जरूरत है तो मैं देने को तैयार हूं। पूनिया ने कहा कि गहलोत अब बे-सिर पैर की बातें कर रहे है। इतने बड़े राजनीतिक कद वाले व्यक्ति अगर बे-सिर पैर की बातें करते है तो

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस वार्ता आयोजित की।

समझ से परे है। आखिर गहलोत क्या करना चाहते है यह समझ से परे है, वे विपक्ष का धर्म तक भूल गए है। उनकी बातों से ऐसा प्रतित होता है कि गहलोत एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने की बात सहन नहीं कर पा रहे। गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना फंडामेंटल राइट्स समझते है।

भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत ने आज अपने कालखंड को याद दिला दिया, गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान महिला अपराध, दुष्कर्म, बच्चों की तस्करी, पेपरलीक में देश में नंबर वन था। गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान में रोज 17 दुष्कर्म की वारदात हो रही थी, 8 हत्याएं रोज हो रही थी, 2018 से लेकर 2023 तक कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई थी। इन्होंने राजस्थान जैसे शांति प्रिय प्रदेश में 10 प्रतिशत अधिक सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। कोरोनाकाल में जहां रोज 162 मौतें हो रही थी, इनकी सरकार बाड़े में बंद थी, अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ राजद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज करवाने वाले गहलोत की प्रेसवार्ता सिर्फ दिखावटी थी, हकीकत तो वे अपने ही नेताओं को उजागर कर रहे थे। गहलोत घूम फिरकर 2020 में चले जाते है। राजस्थान में अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपरलीक जैसे मामलों के चलते गहलोत जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा था।

पूनिया ने कहा कि उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि काम कुछ करना नहीं और अखबारों की सुर्खियों में अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए बयानबाजी करते है। कांग्रेस पार्टी की फितरत है कि सत्ता से बाहर होने पर उनको कुछ समझ नहीं आता।उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड पर सवाल उठाने वाले गहलोत भूल गए कि यह अपराध गहलोत के कार्यकाल में ही हुआ।

पी.एम. मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ याचिका में बहस पूरी

- **याचिका में नागरिकता अधिनियम में संशोधन से देश की एकता व अखंडता को खतरे में डालने और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है**
- **अदालत ने मामले में बाद में फैसला देना तय किया है**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर दायर याचिका पर बहस पूरी हो गई। है। अदालत ने मामले में बाद में फैसला देना तय किया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश याचिकाकर्ता अधिवक्ता पूरणचन्द्र सेन की याचिका पर दिया। याचिका में नागरिकता अधिनियम में संशोधन से देश की एकता व अखंडता को खतरे में डालने और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी आरडी रस्तोगी ने पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार की ओर से एजी राजेन्द्र प्रसाद ने पैरवी की। केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी रस्तोगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है।

वहीं देश में बनने वाला कोई भी कानून गृह मंत्री, कानून मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं। कानून संसद की ओर से बनाया जाता है। ऐसे में पीएम मोदी और दोनों मंत्रियों पर आरोप लगाना गलत है। इसके अलावा याचिकाकर्ता स्वयं संसद में मौजूद नहीं था तो मिलीभगत का आरोप कैसे लगा सकता है। वहीं नागरिकता अधिनियम में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। याचिकाकर्ता ने कानून का दुरुपयोग किया है। ऐसे में उसकी याचिका को भारी हर्जाने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। दूसरी ओर महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो मुद्दा उठाया है, वह संबंधित निचली अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसलिए निचली अदालत ने परिवाद को खारिज कर कोई गलती नहीं की है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका पर फैसला बाद में देना तय किया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद-15 के विपरीत है। इस संशोधन के कारण मुस्लिमों के साथ भेदभाव हुआ है। देशभर में अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ है और देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचा है। संशोधन के बाद देशभर में अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस ने या तो एफआईआर दर्ज नहीं की या फिर आधी-अधूरी की है। इसके अलावा निचली अदालत ने भी मामले में दायर परिवाद को खारिज कर कानून की त्रुटि की है।

शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन आज

जयपुर। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने संघ के सक्रिय पदाधिकारियों की आपात बैठक में लिया विरोध प्रदर्शन का निर्णय। राज्य सरकार बार-बार बजट में मंत्रालयिक कर्मचारी के हितों के लिए घोषणाएँ करके उन्हें लागू नहीं कर रही है। कर्मचारी संघ द्वारा समय-समय पर इस हेतु सरकार को अवगत कराया है, महासंघ एकीकृत भी सरकार से कई बार वार्ता कर मंत्रालयिक कर्मचारियों की वाजिब मांगों को शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया है। सरकार की वाजिब मांगों के प्रति अनदेखी कर्मचारियों के साथ सरासर धोखा और वादा खिलाफी है। इसी कड़ी में संघ के सचिव कृष्णेन्दु चटर्जी ने बताया की आज दिनांक 23 सितंबर को जलदाय विभाग में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रालयिक कर्मचारी की प्रमुख मांग सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे- 4200 कर तदनुसार अन्य पदों का उन्नयन, मंत्रालयिक कर्मचारी का कैडर रिव्यू, एसीपी में देय 9,18,27 वर्ष के लाभ को 8,16,24,32 वर्ष देना सहित।

शहरी सेवा शिविरों में योजनाओं का एक ही स्थान पर मिल रहा है लाभ : सीएम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा नगर निगम और नगर पालिका हमीरगढ़ में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का अवलोकन किया

भीलवाड़ा, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को भीलवाड़ा नगर निगम और नगर पालिका हमीरगढ़ में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तकसेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेशभर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को एक ही स्थान पर सभी जरूरी दस्तावेज और सेवाएं मुहैया कराना है। इनमें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के साथ-साथ पेंशन, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत और स्वच्छता जैसे कार्य भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहेब आंबेडकर की अंत्योदय की भावना को धरातल पर उतारने के लिए ये शिविर प्रभावी साधन बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से

कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का स्वागत किया गया।

अपील की कि वे इन शिविरों का भरपूर लाभ उठाएं और अपने आस-पास के पात्र व्यक्तियों को भी इसका लाभ दिलाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय भ्रष्टाचार चरम पर था और पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं के सपनों को तोड़ा। वहीं वर्तमान सरकार में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के हित में योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीते दो वर्षों में एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, जिससे सरकार की पारदर्शिता और प्रतिबद्धता सिद्ध होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जबरन या प्रलोभन देकर किए जा रहे धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया है। इससे सामाजिक समरसता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। शर्मा ने बताया कि

- **'पूर्व सरकार के समय भ्रष्टाचार चरम पर था और पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं के सपनों को तोड़ा'**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह संदेश केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकार का प्रतीक है। शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया और उन्हें चेक व पट्टे वितरित किए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आमजन को घर बैठे सभी सेवाएं मिलें। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक गोपाल खंडेलवाल, अशोक कोठारी, लादूराम पीतलिया, उदयलाल भड़ाना सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे।

कोटा में जिंक व्यापारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई

इनकम टैक्स की टीम ने व्यापारी की फैक्टरी पर पहुंचकर फाइलें खंगाली

कोटा, (निसं)। इनकम टैक्स की टीम ने कोटा में एक प्रतिष्ठित जिंक व्यापारी के ठिकानों पर छापा मारा है। टीम मंगलवार सुबह ही व्यापारी की फैक्टरी पर पहुंच गई थी। यहां पर अधिकारियों ने दबिश दी है। साथ ही कारखाने की जुड़ी सभी फाइलों को खंगाला जा रहा है।

कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि इनकम टैक्स की टीम ने उनसे जाप्ता मांगा था और उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया है। हालांकि इनकम टैक्स की टीम की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाहर खड़ी हुई सभी गाड़ियां दिल्ली से यहां पर आई हैं। इनमें से कुछ गाड़ियां एक-दो दिन पहले ही कोटा पहुंच गई थी, जबकि ज्यादातर गाड़ियां सोमवार शाम को यहां पर आई हैं। आयकर विभाग की टीम अंदर दस्तावेज और कंप्यूटर रिकॉर्ड की जांच कर रही है। इस टीम की करीब दो दर्जन के आसपास गाड़ियां कोटा में मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में सिक्योरिटी के लिए एक कंपनी के सुरक्षाकर्मी तैनात हैं जिनका ड्यूटी टाईम सुबह बदल गया था। इसमें मॉर्निंग शिफ्ट वाले लोग पहुंच गए थे लेकिन जब टीम यहां पर आई तब उन्होंने किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। इसी दौरान दूसरी टीम के लोग वहां फंस गए। सभी लोगों के मोबाइल बंद कर दिए। ऐसे में कंपनी के सुपरवाईजर को उनके परिजन फोन करने लगे। इसके बाद सिक्योरिटी कंपनी के लोग भी यहां पर पहुंच गए। इसी दौरान बिजली के बिल की रीडिंग लेने पहुंचे एक व्यक्ति को भी अंदर ही रोक लिया गया। फैक्टरी में पूरी तरह से मशीनरी को बंद रखा गया है। वहीं मजदूर को भी एक तरफ कोने में बैठा दिया था। इसके अलावा अन्य सभी स्टॉफ को भी ऑफिस से दूर रखा गया था। इन सब लोगों को सुबह 11.40 पर रिलीज किया गया है। सिक्योरिटी की ड्यूटी दे रहे एक कर्मचारी का कहना है कि उनके मोबाइल फोन भी बंद कर दिए थे और यह टीम सुबह 6 बजे ही पहुंची थी।

सियार के हमले से बालक घायल

बयाना/भरतपुर, (निसं)। उपखंड के वमनपुरा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सियार (गेदुआ) के हमले में एक 12 वर्षीय बालक घायल हो गया। घायल बालक मंकेज, निवासी कैर, मंगलवार को स्कूल से लौटते समय रास्ते में सियार का शिकार बन गया। मंकेज के चाचा रामसिंह ने बताया कि बच्चा स्कूल से घर लौट रहा था, तभी गांव के रास्ते में अचानक एक सियार ने उस पर हमला कर दिया।

बयाना उपजिला अस्पताल में चोर सक्रिय

बयाना/भरतपुर, (निसं)। उप जिला अस्पताल बयाना में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मंगलवार को अस्पताल परिसर में इलाज के लिए आए एक मरीज की जेब से अज्ञात चोर 25 हजार रुपये निकालकर फरार हो गया। इस घटना से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जेबें टटोलते नजर आए।

मूल रूप से उपखंड के मुआवली गांव निवासी जगदीश जाटव ने बताया कि वह मंगलवार को ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने आया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे की जेब से 25 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने बताया कि यह रकम उसे बयाना के रीको क्षेत्र में ट्रक से पत्थर डालने की एवज में मिली थी। जगदीश ने घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज

- **मरीज की जेब से 25 हजार रुपये पार किये**

कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी कुछ महीने पूर्व अस्पताल परिसर में ही निःशुल्क दवा काउंटर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति के थैले में चीरा लगाकर रुपये चोरी करने की घटना सामने आई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों में डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

मांगों को लेकर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में सीएम के दौरे के बीच बीलिया कलां गांव का एक युवक कस्बे में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। देर शाम तक युवक टावर पर मौजूद रहा। नीचे लोगों की भीड़ जुटी है।

जानकारी अनुसार, बीलियाकलां का निवासी सूरज माली मंगलवार दोपहर हमीरगढ़ में रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित मोबाइल कंपनी के टावर पर चढ़ गया। देखते ही देखती बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर भीड़ जुट गई। उधर, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के सीएम ड्यूटी में व्यस्त होने से वहां कोई अधिकारी नहीं पहुंच पाया। पुलिस को जानकारी मिली कि युवक शुभ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाते हुये कार्रवाई की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच समझाइश का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर युवक का आरोप है कि क्षेत्र में संचालित प्रोसेस हाउस और फैक्ट्रियों द्वारा खुलेआम नियमों की अवहेलना करते हुए ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग प्रभावी कार्यवाही नहीं करते, जिसके कारण आस पास के ग्रामीणों का जीवन दूभर हो रहा है। पीड़ित युवक का कहना था कि कोयले की राख, तेज ध्वनि और दुर्गंध की वजह से उसकी गेंदे के फूल की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कई बार सीएम और पीएम तक को शिकायत भेजने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो पाई, जिसके कारण उसे यह कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा है।

काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई हुई

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस संदीप शाह की कोर्ट में वर्ष 1998 के काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई हुई। इसमें राज्य सरकार की ओर से दायर लीव टू अपील और सलमान खान की ओर से सजा के फैसले को चुनौती देने की याचिका शामिल है। इन दोनों पर एक साथ विचार हुआ। हालांकि, मामले में सरकारी वकील ने समय मांगा। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। मामले में बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पेश लीव टू अपील और सलमान खान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से मिली सजा के खिलाफ अपील, जो पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर की गई थी।

मोरेल नदी पर टूटी सड़क से 40 गांवों का सम्पर्क कटा

बौंली-बामनवास, (निसं)। क्षेत्र के बरनाला तहसील अंतर्गत टिगरिया गांव के पास मोरेल नदी पर टूटी सड़क व पुलिया के कारण बौंली एवं बामनवास उपखंड क्षेत्र के करीब 40 गांवों का आपसी संपर्क कटा हुआ है। इस कारण छात्र-छात्राओं को विद्यालयों में अध्ययन करने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर वाहन चालकों का तो आवागमन ही बहुत कठिन हो गया है। इस मामले को लेकर स्थानीय ग्राामीणों ने भडौती के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी अविनाश कुमार व बहादुर सिंह गुर्जर को भी सड़क मार्ग ठीक करने को लेकर अवगत कराया था लेकिन एक माह गुजर जाने के बाद भी सड़क मार्ग ठीक नहीं हो पाया, जबकि

छात्र-छात्राओं को विद्यालयों में जाने में परेशानी हो रही है।

अधिकारियों ने सड़क मार्ग को जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों ने इस सड़क मार्ग को शीघ्र ठीक करा कर बौंली व बामनवास क्षेत्र के 40 गांवों का आगमन सुचारु कराने की मांग की है।

साढ़े चार हजार प्रिंसिपल के तबादले किये

बीकानेर, (निसं)। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बड़ी संख्या में ट्रांसफर करने के लिए 508 पेज की लिस्ट पिछले दिनों तैयार की थी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के ई-हस्ताक्षर किए गए। इसमें साढ़े चार हजार प्रिंसिपल के तबादले किये गये हैं।

स्थानान्तरित प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से रिलीव करने और जॉइन करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों के शिक्षा प्रिंसिपल बदले हैं। इसमें अधिकांश टीचर्स को उनकी मनपसंद जगह लगाने का प्रयास किया गया है। वहीं बड़ी संख्या में प्रिंसिपल को शहर से गांवों में भी भेजा गया है। गत वर्षों में जिन स्कूलों को सीनियर सैकंडरी में क्रमोन्नत किया गया था, उनमें भी अब प्रिंसिपल लगा दिए गए हैं। शहर के अंदर पिछले कई सालों से जमे सैकड़ों प्रिंसिपल को अब गांवों में पदस्थापित किया गया है।

प्रिंसिपल ट्रांसफर से पहले भाजपा के विधायकों से एक तय संख्या में डिजायर ली गई थी। भाजपा विधायक जहां नहीं हैं, वहां भाजपा के प्रत्याशी रहे नेता से या फिर सांसद से डिजायर ली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में विधायकों ने डिजायर भी दी और एक तय संख्या में अलग से नाम भी दिए। इन्हीं नामों को ट्रांसफर लिस्ट में जगह दी गई है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के समक्ष ये ट्रांसफर लिस्ट करीब 20 दिन पहले ही रख दी गई थी। बाद में इसे विधानसभा सत्र के चलते रोक दिया गया था। फिर श्राद्ध पक्ष के कारण लिस्ट रोकी गई, लेकिन अब नवरात्रि के पहले ही दिन प्रिंसिपल को नए स्कूलों में पदस्थापित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए स्वीकृति जारी की और देर रात ये लिस्ट जारी हो गई। आदेश में साफ लिखा गया है कि राज्य सरकार के पत्र की पालना में ये ट्रांसफर किए गए हैं।

केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल का जायजा लिया

दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात देंगे : शेखावत

जोधपुर, (कासं)। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नए एयरपोर्ट टर्मिनल को जोधपुरवासियों को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि टर्मिनल का कार्य अंतिम चरण में है और अक्टूबर तक इसे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। शेखावत ने मंगलवार को निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से कहा कि नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद एक साथ 13 फ्लाइट्स का संचालन संभव होगा, जिससे शहर की एयर कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। यात्रियों को बिजली, पानी और अन्य सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अब तक तीन बड़ी दिवाली की सौगातें दी हैं, पहली जीएसटी लागू करके, दूसरी दीयों की रोशनी से और तीसरी जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल के रूप में। उन्होंने बताया कि केंद्र के आग्रह पर राज्य सरकार ने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग करने वाले विमानों पर वेट टैक्स में 26-27 प्रतिशत तक की छूट दी है। इस निर्णय से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की तुलना में यहां फ्यूल सस्ता होगा और इसका सीधा लाभ विमानन उद्योग को मिलेगा। शेखावत ने कहा कि इस कदम से जोधपुर में एयर ट्रैफिक में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। फिलहाल, सुबह व शाम दिल्ली और मुंबई के लिए नियमित फ्लाइट उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, बल्कि जोधपुर के एलिवेटेड रोड और रिंग रोड परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इससे शहर के ट्रैफिक प्रबंधन में व्यापक सुधार होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में भारत में एविएशन सेक्टर में बड़े विस्तार की संभावना है। उन्होंने कहा कि टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस नए जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल से संचालन शुरू करेगी। जैसे ही यह टर्मिनल बिल्डिंग पूरी होगी, एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी होगी और इसके बाद निजी कंपनियां भी यहां संचालन में रुचि दिखाएंगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल पूरे देश में एक हजार से कम विमान संचालित हो रहे हैं, लेकिन आने वाले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एविएशन उद्योग में अभूतपूर्व उछाल देखने को मिलेगा। इस दौरान करीब 3 हजार नए विमानों के लिए आवेदन किया गया है। इस दौरान जोधपुर एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य अशोक माथुर, प्रकाश जीरावाला, किशोर सिंह सोलंकी, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही नए एयरपोर्ट टर्मिनल के कार्य से जुड़े अधिकारी साथ रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एयर, रोड और रेल कनेक्टिविटी के साथ अब जोधपुर में नए टूरिस्ट स्पॉट विकसित किए जाएंगे, ताकि पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा मिल सके। उनके अनुसार किसी भी विकसित देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन अहम भूमिका निभाता है और इसी दिशा में जोधपुर को नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर एक करोड़ की सायबर ठगी, आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। सायबर पुलिस टीम ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर एक करोड़ चार लाख की सायबर ठगी के दर्ज प्रकरण में कार्यवाही करते हुए सायबर ठगी के आरोपी को कुन्हाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 6 जून को परिवादी विनोद कुमार जैन ने रिपोर्ट दी। परिवादी ने रिपोर्ट में कहा कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर उससे 1 करोड़ 4 लाख की सायबर ठगी की है। परिवादी ने अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रेडिंग के नाम पर रूपये डाले है। शहर एसपी ने कहा कि परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में सायबर थाने के पुलिस उपअधीक्षक विनोद कुमार के सुपरविजन में सायबर थाने के थानाधिकारी सतीश चन्द के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी

कोटा सायबर पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया।

ने बताया कि गठित टीम ने मामले में कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली बूंदी के लंका गेट निवासी महावीर सुखवाल उर्फ डेनी को कोटा के कुन्हाड़ी इलाके के लैण्डमार्क सिटी से डिटेन कर प्रकरण में गिरफ्तार किया।

शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने परिवादी के साथ हुई 1 करोड़ 4 लाख की ठगी राशि में से बैंकों से पत्राचार कर 10 लाख रूपये की राशि को होल्ड करवाया एवं 12 लाख रूपये परिवादी के बैंक में रिफंड करवाये। शहर एसपी नें बताया कि

- **बारह लाख रूपये रिफंड कराये, 10 लाख रूपये बैंक खातों में होल्ड कराये**
- **परिवादी ने अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रेडिंग के नाम पर रूपये डाले थे**
- **पकड़े गये आरोपी को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया**

पकड़े गये आरोपी महावीर सुखवाल को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पकड़े गये आरोपी के पास से 5 मोबाइल बरामद हुए है, मामले में अन्य आरोपियों एवं सायबर ठगी की शेष राशि बरामद करने के लिये अनुसंधान जारी है।

शहर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्वयं के खाते में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सायबर ठगी की राशि को डलवाता एवं अपने परिचित व रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में वह राशि इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से ट्रांसफर कर देता था, फिर उस राशि को चैक व एटीएम द्वारा निकाल लेता था। शहर एसपी ने बताया कि आरोपी उस राशि का उपयोग यूएसडीटी ऑनलाइन करंसी खरीदने एंव लग्जरी स्टाइल में रहने के लिये करता था। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

सीढ़ियों से गिरने से आरएसी जवान की मौत

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में सीढ़ियों से गिरने से आरएसी जवान की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरएसी जवान संजय कुमार सीढ़ियों पर चढ़ते समय पैर फिसलने से गिर गया, जिसे अचेतावस्था में उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान जवान की मौत हो गई।

दादाबाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि मूल रूप से झुंझनू के मंडावा निवासी संजय कुमार (44) जो हाल कोटा आरएसी बटालियन में डेल्टा कंपनी में पोस्टेड था। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में सामने आया कि जवान सीढ़ियों पर चढ़ते समय पैर फिसलने से गिरकर अचेत हो गया, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। थानाधिकारी ने बताया कि फिलहाल मौत होने का कोई कारण सामने नही आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मौत के कारण सामने आ पायेगें। मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

OFFICE MUNICIPAL COUNCIL CHOMU (JAIPUR)
Tel-01423-220036 e-mail:chomu.jaipur@yahoo.com
Sr. No. : NPC/2025/1877 Date : 19.09.2025
Notice Inviting Bid
Bids for "Supply of 01 JCB and 01 dumper along with operator/driver, diesel-oil, repair and other expenses for sending all types of wet and dry waste from the garbage collection site located at NH 52, Lal Kui, Ward No. 44 in the Municipal Council area to the garbage collection center located at Seva Pura, Jaipur." are invited interested bidders upto 06.00 PM on 19.09.2025 Dated. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in, https://eproc.rajasthan.gov.in) of the state. The Bid Value are 125.00 Lacs.
NIB CODE : DLB2526A6180
UBN NO. : DLB2526SLOB19110
COMMISSIONER
MUNICIPAL COUNCIL CHOMU
Raj.Samwad/C/25/10687

Office of the Superintending Engineer PHED Circle Jhalawar (Raj.)
NOTICE INVITING Bid No. 25/2025-26
NIB No. PHE2526A3166
Bids for Work of Augmentation of RWSS SARDA, Gram Panchayat SARDA Panchayat Samiti Aklera (on risk and cost basis) Sub Division Aklera & KOLUKHERI KALAN, Gram Panchayat KOLUKHERI KALAN Panchayat Samiti Manoharthana of Sub division Manoharthana to provide FHTC including one year Defect Liability period under JJM in the jurisdiction of PHED Division Jhalawar District Jhalawar are invited from interested bidder's upto 25.09.2025 at 18.00 Hours. Other particulars of the bid may be visited on the www.dipr.rajasthan.gov.in, http://rajwater.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in and http://eproc.rajasthan.gov.in. Departmental websites.
1. UBN No. PHE2526WSOB06415 Cost Rs. 131.76 Lac
2. UBN No. PHE2526WSOB06417 Cost Rs. 105.40 Lac
Superintending Engineer
PHED Circle Jhalawar
DIPR/C/13668/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-करौली
क्रमांक-Rajkaj- 2564-84 दिनांक-12.09.2025
निविदा सूचना संख्या - 11/2025-26
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सडक मरम्मत कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण/ डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि के पंजीकृत संवेदको जो कि राज्य सरकार के "एए", "ए", "बी", "सी", डी श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण बेब साईट "www.sppp.rajasthan.gov.in" & "www.dipronline.org पर देखा जा सकता है।
NIB Code :- PWD2526A 3254
UBN No- 1. PWD2526WSOB 12190
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड करौली
DIPR/C/13764/2025

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दुरभाष स.0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट. www-udaipurmc.org
क्रमांक : निविजा/2025–26/ई –27 दिनांक :– 23.09.2025
(ई–भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या – ई 27/2025–26
नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्यो हेतु कुल राशि रु0 105.00 लाख के कुल 02 कार्यो हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा के कार्यो की प्रारम्भ तिथि 23.09.2025 एवं अंतिम तिथि 03.10.2025 तथा निविदा खुलने की तिथी 06.10.2025 रहेगी निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है।
UBN No. UNP2526WSOB00088
अधीक्षण अभियन्ता
नगर निगम, उदयपुर
राज.संवाद/सी/25/10706

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान
E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419
क्रमांक :–न.प.सु/विकास शाखा/2025/6374 दिनांक :– 19.09.2025
–: ई–निविदा सूचना–2025–26 :–
नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से निविदा दिनांक 27.09.2025 तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड कमांक (DLB2526WSOB19246), (DLB2526WSOB19247) है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।
आयुक्त
नगर परिषद सुजानगढ
राज.संवाद/सी/25/10680

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEEER P.H.E.D CITY DIV. IV (NORTH) JAIPUR
Email:eenorth4.jai.phed@rajasthan.gov.in Telephone No-0141-2988545
No.: E.E./CD4(N)/2025-26/1750-64 Dated:12/9/2025
Notice Inviting Bid
Bids for work of 1. Annual Rate Contract for the work of transportation of water through Tankers in Bisalpur water supply Benefited areas (Low pressure areas) under the jurisdiction of City Division IV (North) Jaipur 2. Repair and preventive Maintenance of Centrifugal pump sets of pumphouses and their panels and Submersible pump sets and their panel of tubewell in water supply scheme under city Sub Dn-1 (North), Vidhyadhar nagar Jaipur and 3. Repair and preventive Maintenance of Centrifugal pumpsets of pumphouses and their panels and running of Pumphouse VKIA road no 5 Road no 9A, Road no 13 water supply scheme under city Sub Dn-I (North), Vidhyadhar nagar Jaipur under jurisdiction of City Div. IV(North) Jaipur NIT No 25/2025-26 is invited from interested bidders up to 06:00 PM 25.09.2025 Other particulars of the bid may be visited on the www.sppp.rajasthan.gov.in and www.eproc.rajasthan.gov.in of the state website.
UBN Code: PHE 2526 WSRC06561 PHE 2526 WSOB06562 PHE 2526 WSOB06564
Executive Engineer
PHED City Div. IV (North)
Vidhyadhar Nagar Japur
DIPR/C/13850/2025

सार-समाचार

समूहगान प्रतियोगिता आयोजित

कोटा, (निसं)। निजी शिक्षण संस्थान आर.के.पुरम में भगत सिंह शाखा भारत विकास परिषद कोटा के तत्वावधान में सेवा प्रकल्प के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने समूहगान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यह जानकारी शाखा मीडिया प्रभारी पी.पी.गुप्ता ने दी। गुप्ता ने बताया कि समूहगान प्रतियोगिता मां भारती के चित्र पर दीप प्रज्जवलन केसाथ प्रारंभ हुआ। जिसमें तीन स्कूलों की बालिकाओं ने हिस्सा लिया। शाखा अध्यक्ष ओमप्रकाश दुसाद ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उदेश्य विद्यार्थियों में राष्टभक्ति, सांस्कृतिक चेतना और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देना रहा है। इस अवसर पर बालिकाओं ने आकर्षक परिधान में सांस्कृतिक गीतों से बहुत सुंदर प्रस्तुति देकर वातावरण को भावविभोर कर दिया। निर्णायक मण्डल की सदस्य प्रेमलता जैथलिया ने कहा कि हर प्रस्तुति में स्वर व ताल की अद्वितीय झलक मिली, बच्चों ने भारत की विविधता में एकता को गीतों के माध्यम से जीवंत कर दिया। शाखा सचिव ने विजेता टीम महेश्वरी पब्लिक स्कूल की बालिका प्रथम विजेता रही है जिन्हें स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर शाखा अध्यक्ष ओमप्रकाश दुसाद, सचिव अशोक जैथलिया, कोषाध्यक्ष अजय गटटानी, मीडिया प्रभारी पी.पी.गुप्ता, पुरूषोतम माहेश्वरी, सत्यनारायण चाण्डक, आरसी लखोटिया, मधु जैन, तारा झंवर, प्रेमलता जैथलिया आदि उपस्थित रहे। अंत में सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम का संचालन शाखा सचिव अशोक जैथलिया ने किया।

सेवा पखवाड़ा में हेलमेट बांटे

नैनवां (निसं)। हिण्डोली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाडा कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा ज़िलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा,विशिष्ट अतिथि ओम धगांल,अध्यक्षता मण्डल अध्यक्ष कल्याण सिंह सौलंकी ने की इस दौरान रक्तदान शिविर संयोजक विक्रम सिंह हाडा ने बताया कि शिविर में ग्रामीणों,युवाओं व भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ चढकर हिस्सा लिया और 75 यूनिट रक्तदान किया वहीं रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को शिविर संयोजक विक्रम सिंह हाडा कि ओर से सडक सुरक्षा को देखते हेलमेट वितरित किए गए। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष सीताराम सैनी, पूर्व मण्डल अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, प्रभुलाल वर्मा, महामंत्री संजय बरमुण्डा, जितेंद्र सिंह हाडा, रमेश बैरवा, विष्णु योगी, नितेश खटोड, लोकेश, राजेश, महेन्द्र, भैंरूलाल, मनिष, कल्याण सिंह, राधेश्याम मेघवंशी, सुरतान, बंशीलाल सैनी,नन्द किशोर गुर्जर सहित कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कार्यक्रम में भाग लिया।

न्याय की मांग, आमरण अनशन किया

बूंदी (निसं)। बूंदी सदर बाजार कहार मोहल्ले में अतिवृष्टि से मकान के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार की कोई सुध नहीं लेने के विरोध में न्याय की मांग को लेकर परिवार के सदस्य बुधवार से क्षितग्रस्त मकान के बाहर ही आमरण अनशन पर बैठेंगे। रमेश कहार ने बताया कि बुधवार से पीड़ित परिवार के सदस्य रमेश कहार, रूपशंकर कहार, दुर्गा कहार, महावीर कहार,कमलाबाई कहार, रामशोभा बाई, जानकीबाई, रुक्मणी कहार, मोहिनी कहार,डोली कहार कोमल कहार,मंजू कहार आमरण अनशन पर बैठेंगे।राजस्थान बीज निगम के निदेशक चर्मेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने भी अतिवृष्टि से क्षितग्रस्त मकान के गरीब पीड़ित परिवार को अनशन में साथ बैठने का वचन दिया है।इसलिये वे और एनएसयूआई शहर अध्यक्ष अमन राठौर भी पीड़ित परिवार के साथ आमरण अनशन पर रहेंगे।

साहित्यकार ढोडरिया को सम्मानित किया

छबड़ा (निसं)। साहित्य मण्डल श्री नाथद्वारा की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कहानी प्रतियोगिता में टीकमचन्दर ढोडरिया की कहानी को पुरस्कृत किया गया। यह आयोजन डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल के संयोजन में किया गया था। जिसमें कुल 123 प्रविष्ठियाँ प्राप्त हुई थी। पाँच सदस्यीय निर्णायक मण्डल द्वारा कहानियों का पुरस्कार के लिए चयन किया गया, जिसमें टीकमचन्दर ढोडरिया की कहानी रजनी-गंधा को भी पुरस्कृत किया गया। कोटा में साहित्य मण्डल श्रीनाथ द्वारा एवं हॉप सोसायटी कोटा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ढोडरिया को सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि ढोडरिया की विभिन्न विषयों पर अभी सात पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी रचनाएं देश विदेश की पत्र प्रतिकाओं प्रकाशित होती रहती है। आकाश वाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों से भी रचनाएँ प्रसारित होती रहीं हैं।

शहरी सेवा शिविर आज

बूंदी (निसं)। शहरी सेवा शिविर के लिए निर्धारित कार्यक्रमानुसार बूंदी नगर परिषद में 24 सितंबर को वार्ड संख्या 9, 10, 12, 13 व 14 के लिए पुरानी नगर परिषद, लाखेरी नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड संख्या 9 व 10 के लिए अम्बेडकर भवन सुभाष सर्किल, हिण्डोली नगर पालिका में वार्ड संख्या 06 के लिए नगरपालिका कार्यालय हिण्डोली में, इन्द्रगढ नगर पालिका में वार्ड संख्या 6 के लिए नगर पालिका कार्यालय परिसर इन्द्रगढ में शिविर आयोजित होंगे। इसी तरह नगर पालिका देई में वार्ड संख्या 06 के लिए नगर पालिका कार्यालय देई में, नगर पालिका केशवरायपाटन में वार्ड संख्या 5 के लिए चामुण्डा माता जी मंदिर, नगर पालिका कापरेन में वार्ड संख्या 6 के लिए रैन बसेरा बस स्टेण्ड कापरेन तथा नगर पालिका नैनवां में 24 सितंबर को वार्ड संख्या 7 व 8 के लिए नगरपालिका कार्यालय नैनवां में शिविर लगाए जाएंगे।

स्कूल में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

छबड़ा (निसं)। बापचा पुलिस ने बापचा स्कूल में ताला तोडकर एलईडी टीवी व इन्वर्टरचुराने के आरोपी को गिरफ्तार किया। बापचा थानाधिकारी बुद्धराम जाट ने बताया कि एक सितम्बर को उच्च माध्यमिक विद्यालय बापचा के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 26 अगस्त को स्कूल की पुरानी बिल्डिंग से अज्ञात लोगो द्वारा कमरे का ताला तोड़कर टीवी तथा एक इन्वर्टर लुमिनस चोरी कर ली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए गठित की गई टीम ने जगदीश ऐरवाल (37) पुत्र बद्रीलाल निवासी बापचा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। जिसके कब्जे से चुराए गए एलईडी टीवी व इन्वर्टर को बरामद किया। आरोपी से अन्य चोरी की घटनाओ के संबंध में अनुसंधान जारी है।

शिविर आयोजित, कई मामले निपटाए

छबड़ा (निसं)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमे आमजन से संबंधित कार्यों का त्वरित एवं निर्धारित समय अवधि मे निस्तारण किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा आवेदको द्वारा जमा किये जाने वाली राशि मे भी छूट देकर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। ईओ यादवेंद्र यादव के अनुसार को मंगलवार को इंद्रा कॉलोनी के सामुदायिक भवन (दवाई बस्ती) मे शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे नियमन पट्टे के 2, स्ट्रीट लाईट 21 मुख्यमंत्री स्वनिधि के 3, नाम हस्तान्तरण के 7, प्रधानमंत्री स्वनिधि के 1, रसद के 7, विद्युत विभाग के 6, पेंशन के 2, खाद्य सुरक्षा केन3, जनस्वास्थ अभियंत्रिकी विभाग के 11 एवं कुल 16 विभागो द्वारा शिविर मे आमजन की समस्याओ का निस्तारण किया गया।

श्रद्धांजलि दी

छबड़ा (निसं)। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ख़्वानु खान बुधवाली मंगलवार को छबड़ा पहुंचे, यहां उन्होंने कांग्रेस नेता व पूर्व सरपंच बुलंद इकबाल की माता को श्रद्धांजलि दी तथा परिजनों को ढांढस बंधाया। वक्फ कमेटी छबड़ा के सदर साजिद खान ने बताया की वक्फ बोर्ड चेयरमैन ख्वानुखान बुधवाली ने मंगलवार को छबडा पहुंच कर कांग्रेस नेता व पूर्व सरपंच बुलंद इकबाल की माता के निधन पर उनके निजी आवास पर पहुंच कर श्रद्धांजलि देकर परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके बाद उन्होंने समाज के लोगो से मुलाकात कर वक्फ से संबंधित मामलों पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ जिला वक्फ कमेटी बूंदी चेयरमैन इकरामुद्दीन बबलू, जिला वक़्फ़ कमेटी टोंक के चेयरमैन मिर्ज़ा मतीन बेग़, द हेल्पिंग हेंड कोटा के अध्यक्ष अफरोज खान व मौलाना आजाद मानव सेवा संस्थान परिवार के अध्यक्ष शेख बहादुर मौजूद रहे।

दो आरोपी गिरफ्तार

छबड़ा (निसं)। पुलिस द्वारा 4 साल से फरार चल रहे दो जिला स्तरीय आरोपी को गिरफ्तार किया। जिन पर एक-एक हजार रुपए का इनाम घोषित था। सीआई राजेश खटाना ने बताया किनरशी उर्फ नरेश (40) पुत्र मानसिंह किराड निवासी बमौरी जिला गुना व बालस्वरूप किराड (52) पुत्र भगवानसिंह निवासी होडीपुरा झागर थाना धरनावदा जिला गुना म.प्र को गिरफ्तार किया गया।

बाल श्रम व नशीले पदार्थों की बिक्री पर रहे कड़ी निगरानी : जिला कलेक्टर

कोटा, (निसं)। जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं सम्बद्ध समितियों की त्रैमासिक बैठक जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण ईकाई पीयूष समारिया की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।

बैठक में बाल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावी बनाने और बाल हित में श्रेष्ठ कार्य करने के संबंध में निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी विद्यालयों में सुझाव अथवा गरिमा पेटिका ऐसी जगह पर लगाई जाए जहाँ बच्चे आसानी से पहुंच सकें तथा अपनी शिकायत डाल सकें। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि विद्यालय परिसर में चाईल्ड हैल्पलाईन 1098 की जानकारी आवश्यक रूप से प्रदर्शित की जाए। बाल श्रम के प्रकरणों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि ऐसे स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि बालश्रम ना हो पाए।

कोटा जिला कलेक्टर ने त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।

बच्चों में बीच नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम पर चर्चा कर निर्देश दिए कि ऐसे पदार्थों के विक्रय पर सघन निगरानी रहे तथा सभी मेडिकल दुकानों पर सी.सी.टी.वी कैमरे आवश्यक रूप से लगवाने के निर्देश दिये। माध्यमिक एवं प्रारिम्भक शिक्षा द्वारा गुड टच-बेड टच का प्रशिक्षण देने, सुझाव पेटी की अनुपालना, चाईल्ड राईट क्लब की कार्यवाही की जानकारी लेकर इन्हें प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दर्ज प्रकरणों व चालान की स्थिति, दर्ज प्रकरणों में अभियोजन की प्रगति की समीक्षा, पीड़ित बच्चे एवं परिवार को मनोवैज्ञानिक परामर्श काउसंलिग विधिक सहायता एवं गवाह संरक्षण की उपलब्धता की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। गुमशुदा बालकों के दस्तयाब पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट से चर्चा, चाईल्ड हेल्पलाईन की प्रगति की जानकारी ली गई। बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड में लम्बित प्रकरणों पर भी चर्चा की गई। राजकीय एवं गैर राजकीय बाल गृहों व आश्रय गृहों की प्रगति, बच्चों के सम्पूर्ण पुनर्वास पर चर्चा की गई। राजकीय बालिका गृह में शारीरिक शिक्षक लगाने के निर्देश दिए गए।

सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई रामराज मीना ने विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी दी। इस अवसर पर बाल विवाह मुक्त राजस्थान पोस्टर का विमोचन किया गया तथा बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई।

बैठक में अति. जिला कलेक्टर कृष्णा शुक्ला, सीईओ जिला परिषद कमल कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की संयुक्त निदेशक सविता कृष्णिया, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजेन्द्र राठौड़ व सदस्यगण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेन्द्र नागर, राजकीय बालिका गृह अधीक्षक अन्शुल मेहन्दीरत्ता, बाल संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा सहित श्रम विभाग, एक्साइज विभाग, स्काउट गाईड से उपप्रधान यज्ञदत्त हाड़ा, सृष्टि सेवा समिति से भूपेन्द्र सिंह, चाईल्ड हेल्पलाईन काउन्सलर महिमा पांचाल एवं राजकीय-गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों के अधीक्षक उपस्थित रहे।

सेवा पखवाड़ा के तहत जागरूकता रैली निकाली

कोटा, (निसं)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की कड़ी में "सेवा पखवाड़ा" के अंतर्गत भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन के मुख्य आतिथ्य व रामपुरा गांधी चौक पुरानी धानमण्डी व्यापार संघ अध्यक्ष प्रशांत जैन, सचिव निशान कोठारी, संरक्षक रमेश आहूजा के सानिध्य में रामपुरा गाँधी चौक परिसर में आमजन में कढ़ी एवं चावल का वितरण एवं जागरूकता रैली निकालकर व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने व बेचने का आव्हान करते हुए स्वदेशी जागरूकता के लिये पत्रकों का वितरण कर दुकानों पर स्टिकर लगाए गए।

जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी कोटा शहर द्वारा सेवा पखवाड़ा के तहत मनाया जा रहा हैं। सेवा पखवाड़ा की कड़ी में रामपुरा पुरानी धानमण्डी में दुकान-दुकान पर जाकर, व्यापारियों से मिलकर नई जीएसटी बचत उत्सव के तहत होने वाले लाभ से अवगत करवाया गया। स्वदेशी उत्पाद खरीदने व बेचने के लिये आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जीएसटी दरों में सुधार कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया हैं, इससे आमजन को राहत व देश मजबूत बनेगा। जैन ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आह्वान किया है कि राष्ट्र प्रथम की भावना से, देश को मजबूत बनाने के लिये, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये, देश को विकसित भारत बनाने के लिये, मेक इन इंडिया व वॉकल फोर लोकल पर जोर देना होगा, भारतीय उत्पादों को खरीदना व बेचना है, जिससे भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होती जायेगी।

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण, राजस्थान
राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल-कोटा
Website : www.kotamc.org, Email : nnksouth@gmail.com

क्रमांकः- ननि (दक्षिण) को/रा.मे.द./2025/8706-707 दिनांकः- 20.09.2025

-:: आम-सूचना ::-

-:: मेला दशहरा 2025 ::-

132वाँ राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 में मेला प्रांगण के ईस्ट, वेस्ट, नोर्थ जोन में चिंहित स्थानों पर साईज अनुसार फुटपाथ एवं जमीन पर अस्थाई भूमि वर्ष 2025 मेला अवधि (17.10.2025) तक के लिए ठैला, पाटा, मनिहारी एवं अन्य व्यवसायीयों की दिनांक 24.09.2025 से सीमित चिन्हित स्थानों पर "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर रसीदें जारी की जावेगी।

उपायुक्त राजस्व

राज.संवाद/सी/25/10728

कार्यालय नगर पालिका सांगोद जिला कोटा (राज.)

क्रमांक/न.पा.सा/भूमि/2025-26/2539-40 दिनांक:-23.09.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि नगर पालिका सांगोद में निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा पट्टा (कृषि भूमि नियमन) के प्रयोजनार्थ हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। अत: निम्नानुसार व्यक्ति के आवेदन पर किसी को कोई आपत्ति हो तो नगर पालिका कार्यालय में 7 दिवस में मय दस्तावेज अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा बाद मियाद एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

क्र. सं.	नाम/पिता/पति का नाम व पता	कालोनी का नाम	खसरा नं.	साईज (वर्गमीटर)	चतुर्थ सीमाएं			
					उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	श्री असलम हुसैन आत्मज रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सांगोद	शहीद अब्दुल हमीद नगर	पुराना 1619 नया 1852 प्लांट नं. 52A	26.58 (31.77 वर्गगज)	प्लांट नम्बर 52B	रास्ता 30 फीट	रास्ता 30 फीट	प्लांट नम्बर 53

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सांगोद

कार्यालय नगर पालिका सांगोद जिला कोटा (राज.)

क्रमांक/न.पा.सा/भूमि/2025-26/2541-42 दिनांक:-23.09.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि नगर पालिका सांगोद में निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा पट्टा (कृषि भूमि नियमन) के प्रयोजनार्थ हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। अत: निम्नानुसार व्यक्ति के आवेदन पर किसी को कोई आपत्ति हो तो नगर पालिका कार्यालय में 7 दिवस में मय दस्तावेज अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा बाद मियाद एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

क्र. सं.	नाम/पिता/पति का नाम व पता	कालोनी का नाम	खसरा नं.	साईज (वर्गमीटर)	चतुर्थ सीमाएं			
					उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	श्री एजाज हुसैन आत्मज रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सांगोद	शहीद अब्दुल हमीद नगर	पुराना 1619 नया 1852 प्लांट नं. 52B	26.58 (31.77 वर्गगज)	प्लांट नम्बर 46	प्लांट नम्बर 52A	रास्ता 30 फीट	रास्ता 30 फीट

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सांगोद

कोटा दशहरा मेला में मुशायरा, गजल संध्या, कव्वाली जैसे साहित्य कार्यक्रमों को पुन: शुरू करवाये जाने की मांग

कोटा, (निसं)। मुशायरा, गजल संध्या, कव्वाली के कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर 23 सितंबर मंगलवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी कोटा के पदाधिकारियों की ओर से शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी की अगुवाई में कांग्रेसजनों ने जिला कलेक्टर पीयूष समारिया को दशहरा मेला में साहित्य कार्यक्रमों को पुन: शुरू करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन पत्र में शहर जिला अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी सहित वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय दशहरा मेला में अखिल भारतीय मुशायरा, गजल संध्या, कव्वाली जैसे साहित्य व देश-प्रेम से भरपूर कार्यक्रमों को पुन: शुरू करवाया जाने की मांग की। त्यागी ने कलेक्टर पियूष समारिया को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाड़ौती के लाखों लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए कोटा मेला दशहरा में पूर्व की भांति अखिल भारतीय मुशायरा, गजल संध्या, कव्वाली जैसे साहित्य व देश-प्रेम से भरपूर कार्यक्रमों को पुन: शुरू करवाया जाये और नहीं तो नगर निगम प्रशासन अपनी हठधर्मिता अपनाते रहे तो शीघ्र ही कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नही बैठेगा और नगर निगम पर आन्दोलन करेगा। त्यागी ने बताया कि नगर निगम प्रशासन दुर्भावनापूर्ण इन कार्यक्रमों को खत्म करके गलत परम्परा का निर्वहन कर रहा है, मुशायरा, गजल संध्या एवं कव्वाली में राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार शामिल होते थे जिससे कोटा मेला दशहरा की ख्याती (प्रसिद्धि) राष्ट्रीय स्तर के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने ज्ञापन पत्र में कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कोटा दशहरा मेला हमारा रियासतकालीन मेला है, यह हमारी सांस्कृतिक पहचान के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री हुकम चन्द वर्मा व श्री विक्रम कुमावत पुत्र श्री नवरंग लाल वर्मा निवासी आवास संख्या 860 केशवपुरा-4 कोटा (राज.) द्वारा उनके स्वामित्व के आवास संख्या 860 केशवपुरा-4 कोटा (राज.) क्षेत्रफल 450 वर्गफीट को रहन रखकर जना स्मॉल फाईनेंस बैंक से ऋण प्राप्त किया जा रहा है।

यह कि श्री हुकम चन्द वर्मा व श्री विक्रम कुमावत को उक्त आवास श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री नवरंग लाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड उपहार पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त आवास से संबंधित नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी पट्टा (लीज डीड) कही खो गया है।

यह कि श्री हुकम चन्द वर्मा व श्री विक्रम कुमावत द्वारा उक्त सम्पत्ति को रहन रखकर जना स्मॉल फाईनेन्स बैंक शाखा कोटा से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। उक्त सम्पत्ति को रहन करने के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था या अन्य को किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस के भीतर सूचित कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवदीय
कमल गुप्ता एडवोकेट
एम.पी.ए. 53 महावीर नगर द्वितीय कोटा
मो. 9414288889

'कोटा में नए न्यायालय भवन का निर्माण जनवरी-2026 से शुरू होगा'

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को अभिभाषक परिषद कोटा द्वारा आयोजित शेड फ्लोरिंग कार्य के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन को लेकर चल रही तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि भवन का निर्माण कार्य जनवरी 2026 से शुरू कर दिया जाएगा।

सेना की आपत्तियों का समाधान निकलेगा:- बिरला ने कहा कि निर्माण को लेकर सेना की ओर से कुछ आपत्तियाँ आई हैं, जिन पर बातचीत चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपसी संवाद से शीघ्र ही समाधान निकाल लिया जाएगा।

सरकार और संबंधित विभाग इस दिशा में सक्रिय हैं और सभी पक्षों की सहमति से रास्ता तय कर जनवरी 2026 तक काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना अधिवक्ताओं और जनप्रतिनिधियों की आपसी सहमति और राय से ही आगे बढ़ाई जाएगी।

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा भवन:- लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नया न्यायालय भवन अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और आम नागरिकों, सभी की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। यह भवन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से युक्त होगा, ताकि दूर-दराज से आने वाले फरियादियों को सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की मजबूती ही लोकतंत्र की असली ताकत है और यह भवन उसी दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।

इस अवसर पर विधायक संदीप शर्मा, जिला न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास, अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायालय कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित रहे।

अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। ग्रामीण इलाके के अयाना पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 1 किलो 84 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध हथियार व अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस उप अधीक्षक इटावा शिवम जोशी के सुपरविजन में अयाना थाने के उप निरीक्षक उम्मेद सिह ने मय जाप्ता इलाके के चाण्दा नहर के समीप चैंकिग के दौरान बाईक सवार को रोककर संदेह होने पर तलाशी ली तो आरोपी के पास से अवैध मादक पदार्थ 1 किलो 84 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए मोटरसाइकिल को जब्त कर सिमलिया, माल बमोरी थाना मांगरोल निवासी राधेश्याम (50) को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

पश्चिम मध्य रेल

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि.मंडल विधुत अभियंता (सामान्य) पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा संख्याः** ईएल/50/276/2025-26 **कार्य का नामः** कोटा डिवीजन- किर्लोस्कर मेक के पावर कार के डीए सेटों की एस्कॉर्टिंग, एन-रुट ऑपरेशन, समस्या निवारण, LSLRD और 500 केवीए (केओईएल मेक) के डीजी सेट ("बी", -"सी", और "डी" अनुसूची रखरखाव) इसके साथ ही कोटा डिवीजन के प्राथमिक रखरखाव वाले रेक की पावर कारों में दो साल की अवधि के लिए लगे सामान के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध। **अनुमानित लागत (1/4 रु. में):** 2,79,42,092.02, **बयाना राशि (रु. में)** 2,89,700/-, **कार्य समाप्ति अवधिः** 24 माह, **निविदा प्रस्तुत करने एवं खुलने की दिनांक तथा समयः** 13.10.2025 को 15.00 बजे तक एवं खुलने का समय 15.15 बजे, ऑफर केवल ई-टेण्डरिंग के माध्यम से वेबसाईट **http://www.ireps.gov.in** पर स्वीकार किए जायेंगे। निविदादाता के पास क्लास III डिजिटल सिग्नेचर सार्टिफिकेट होना चाहिए एवं आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी निविदा मैनुएली स्वीकार नहीं है। निविदा डालने से पहले टेण्डर दस्तावेजों की स्पेशल कण्डीशन्स एवं शर्तें अवश्य पढ़ लें। **(हस्ता.)**

वरि. मंडल विधुत अभियंता (सामान्य)
पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

'समाज के अंतिम छोर तक उत्कृष्ट सेवा ही लक्ष्य'

आरबीएसके टीम के द्वारा गंभीर हृदय रोगी मासूम बच्चे का ऑपरेशन करवाया है।

कोटा, (निसं)। मंडाना निवासी एक मजदूर दंपति का छह माह का पुत्र मानविक, गंभीर हृदय रोग से पीड़ित होकर जीवन-मृत्यु के बीच झूल रहा था। सांस फूलने और कमजोर शारीरिक वृद्धि के चलते परिवार निराश हो चुका था। तभी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) टीम ने इस नन्ही जान को जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने का बीड़ा उठाया।

खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोटा डॉ. प्रभाकर व्यास के नेतृत्व में कार्यरत आरबीएसके टीम की चिकित्सक डॉ. रुचि चित्तौड़ा एवं डॉ.परवेज अख्तर ने सघन निरीक्षण के दौरान मानविक की गंभीर स्थिति को पहचाना। आवश्यक जांचों में पता चला कि बालक के दिल में छेद है और उपचार के लिए ऑपरेशन अनिवार्य है। स्थिति संज्ञान में आते ही डॉ.व्यास ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा डॉ.नरेंद्र नागर, आरसीएचओ डॉ.रमेश करगवाल और सीएचसी मंडाना प्रभारी डॉ.नरेश मेवाडा से सामंजस्य स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही शुरू करवाई। तत्पश्चात 23 जून 2025 को सुधा हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. पलकेश द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। लंबे फॉलो-अप के बाद अब मानविक पूरी तरह स्वस्थ है और परिवार के लिए खुशियों का सहारा बन गया है। इस बीच, लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी लगातार बच्चे की स्थिति से लेकर उपचार एवं ऑपरेशन पश्चात स्वास्थ्य लाभ तक जानकारी लेती रही। हाल ही में मंडाना में आयोजित मेगा शिविर के दौरान उन्होंने मानविक के परिवार से भेंटकर बच्चे को कपड़े, उपहार और स्वस्थ भविष्य का आशीर्वाद दिया। कल्पना देवी ने कहा कि हमारा लक्ष्य समाज के अंतिम छोर तक अभावग्रस्त व्यक्ति को उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध कराना है। इसके लिए हम पूर्णतया कटिबद्ध हैं।

कार्यालय नगर पालिका अन्ता जिला-बारां (राज.)

क्रमांक:-न.पा.अ./भूमि/2025/967-970 दिनांक-28.7.2025

प्ररूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)

लोक सूचना

श्री मोहम्मद इकबाल पुत्र श्री नन्हे खॉ जाति मुसलमान निवासी अन्ता जिला बारां (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के व्यवसायिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला-बारां तहसील-अन्ता	राजस्व ग्राम बमोरी अन्ता पटवार हल्का बमोरी अंता, तह. अन्ता	667 रकबा 1.77 है.	501.51 वर्गमीटर

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज....को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी नगरपालिका अन्ता

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 1717 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 23.9.25

भूखण्ड संख्या 1-एम-41ए महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता को किया गया था। इस भूखण्ड का पंजीयन श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता के नाम दिनांक 26.04.2017 को अपने पक्ष में करवाया किया गया। पंजीयन उपरांत श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 12.07.2024 को श्री कुशल बोहरा पुत्र श्री राम किशोर बोहरा एवं श्रीमती अम्बिका बोहरा पुत्री श्री धुलीचन्द बोहरा पत्नी श्री कुशल बोहरा को संयुक्त रूप से किया गया। श्री कुशल बोहरा पुत्र श्री राम किशोर बोहरा एवं श्रीमती अम्बिका बोहरा पुत्री श्री धुलीचन्द बोहरा पत्नी श्री कुशल बोहरा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 1-एम-41ए महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त भूखण्ड के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कुशल बोहर पुत्र श्री राम किशोर बोहरा एवं श्रीमती अम्बिका बोहरा पुत्री श्री धुलीचन्द बोहरा पत्नी श्री कुशल बोहरा का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त भूखण्ड के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कुशल बोहरा पुत्र श्री राम किशोर बोहरा एवं श्रीमती अम्बिका बोहरा पुत्री श्री धुलीचन्द बोहरा पत्नी श्री कुशल बोहरा का नाम संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूखण्ड के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कुशल बोहरा पुत्र श्री राम किशोर बोहरा एवं श्रीमती अम्बिका बोहरा पुत्री श्री धुलीचन्द बोहरा पत्नी श्री कुशल बोहरा के नाम संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया जाएेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/4472 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक:-20.9.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 03 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्री मीना बाई पत्नी श्री परमानन्द गुर्जर जाति गुर्जर निवासी गांधी नगर छबड़ा जिला (बारां)	162	सरस्वती कालोनी छबड़ा	149	20x40=800

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/4475 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक:-20.9.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 03 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्री रामभरोस आत्मज श्री माणकचंद माली जाति माली निवासी लोटा भैरु छबड़ा जिला (बारां)	588	भगवती विहार कालोनी	06	20x40=800

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/4447 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक:-20.9.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 03 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्रीमती चमेली बाई पत्नी श्री धन्नालाल जाति रैगर निवासी छबड़ा तह. छबड़ा जिला (बारां)	630	उज्जवल विहार कालोनी	54A	20x40=800

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/4404 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक:-18.9.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 03 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्री पवन मीणा आत्मज श्री प्रेमनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तह. छबड़ा जिला (बारां)	697	ऑफिसर्स नगर कालोनी	171A	20x40=800

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

भारत अजेय नहीं है और बुधवार को जब उनकी टीम एशिया कप सुपर चार के मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन से भिड़ेंगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने पिछले चार मैचों में क्या हासिल किया है। **– फिल सिमंस**

बांग्लादेशी कोच, भारत से होने वाले मुकाबले को लेकर।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी

अमन सहरावत

भारतीय कुश्ती महासंघ ने सोमवार 22 सितंबर 2025 को पेरिस ओलंपिक के ब्रान्ज मेडल विजेता अमन सहरावत को वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वीकार्य वजन सीम पर खरा नहीं उतर पाने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेकिन प्रतियोगिता के दिन उनका वजन 1.7 ज्यादा निकला। जिस कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। डब्ल्यूएफआई ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जगरेब में चार कोच मौजूद थे, लेकिन वे वजन प्रबंधन पर नजर नहीं रख पाए और इसके मद्देनजर उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

क्या आप जानते हैं ?... टेस्ट क्रिकेट इतिहास का पहला टेस्ट इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के मध्य 1877 में मेलबोर्न में खेला गया था। इसे ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीता।

फाइनल के लिए जगह पक्की करने उतरेगा भारत

दुबई, 23 सितंबर। प्रशंसकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि कल रात भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला है, और यह एक शानदार मैच है। सुपर फोर का माहौल गरमा रहा है और हर तरफ़ चर्चा है। भारत अब तक अजेय रहते हुए मोर की तरह आगे बढ़ रहा है, जबकि बांग्लादेश कुछ आसान जीत के बाद जोश में है। लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो, यह एकतरफा मुकाबला रहा है। 17 टी20, 16 भारतीय जीतें, और बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक जीत-2019 में, जब बेन स्टोक्स अंपायरों से मिन्नतें कर रहे थे और टिकटॉक पर अभी तक कोई हलचल नहीं हुई थी।

भारत वे खुश हो रहे हैं। शीर्ष पर अभिषेक शर्मा ऐसे धमाल मचा रहे हैं जैसे उन्हें कोई ट्रेन पकड़नी हो-पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंदों पर 74 रन? टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बेहतरीन पारी। दूसरे छोर पर शुभमन गिल कमाल के हैं – ऐसे खेलते हैं जैसे उनके पास दुनिया का सारा समय हो। फिर कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, जो मजे के लिए रिवर्स स्कूपिंग करते हैं, और तिलक वर्मा चुपचाप गेंद को घुमाते हैं। संजू सैमसन छिपकर खेलते हैं, हार्दिक पांड्या अपनी लय में आते हैं, शिवम दुबे स्विंग करते हैं-ये बल्लेबाजी की गहराई है जो कई दिनों तक टिकेगी।

और गेंदबाजी-इसे मत भूलना। कुलदीप यादव गेंद को घुमाते हैं, वरुण चक्रवर्ती अपनी चालों से रहस्यमयी हैं, और जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अभी तक अपनी जगह नहीं बनाई है, लेकिन चिंता न करें-उनके पास तूफ़ानी गेंदबाजी है। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को सीम-अप के साथ जोड़ दें, तो आपके पास एक अच्छी टीम है।

अब, बांग्लादेश यहां संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है। वे मजबूत रहे हैं। सैफ हसन ने श्रीलंका के खिलाफ 61 रनों की शानदार पारी खेली है, तंजीद हसन शीर्ष क्रम में व्यस्त हैं, और लिटन दास उनके कप्तान हैं, जो हमेशा खेल में बने रहते हैं। तौहीद हृदोय लगातार रन बना रहे हैं, चार मैचों में 127 रन बना चुके हैं – वो भी पूरी फॉर्म में। और जैकर अली को नजरअंदाज मत कीजिए, जिन्हें आखिरी ओवरों में धमाकेदार पारी खेलना पसंद है।

गेंदबाजी? मुस्तफिजुर रहमान-द फ़िज-धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं, सात विकेट ले चुके हैं, वो भी धीमी गेंदों से जो बल्लेबाजों को बेबस दिखाती हैं। तस्कीन अहमद अपनी लेंथ पर गेंदें मार रहे हैं, महेदी हसन की स्पिन गेंदें नियंत्रण में हैं, और अगर पिच पकड़ती है, तो खेल शुरू हो सकता है।

पिच की बात करें तो-दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक अजीबोगरीब पुरानी जगह है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मूवमेंट होती है, फिर धीरे-धीरे सपाट हो जाती है। बीच के ओवरों में स्पिनरों को थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है-शाम को ओस पड़ने से लक्ष्य का पीछा करने वालों के लिए काम आसान हो जाता है। यहाँ सात में से पाँच मैच बाद में बल्लेबाज़ी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो, टॉस जीतो, डटे रहो, और जीत का पीछा करो। आसान है।

मौसम गर्मी, चिपचिपाहट, बारिश नहीं। खूब पसीना आ रहा है, इसलिए तौलिया साथ ले आओ।

तो फैसला क्या है? भारत प्रबल दावेदार है-अजेय, आत्मविश्वास से भरपूर, बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दबदबा। बांग्लादेश के पास मैच में उलटफेर करने के लिए हथियार हैं, खासकर अगर उनके गेंदबाज कमाल कर दें, लेकिन इतिहास उनके खिलाफ है। भारत इस प्रतिद्वंद्विता में सालों से दबदबा बनाए हुए है, और मौजूदा फ़ॉर्म को देखते हुए, उन्हें यह सिलसिला जारी रखना चाहिए।

लेकिन थोड़े-बहुत नाटक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दुबई में रात में दूधिया रोशनी में होने वाला यह मैच, दर्शकों का शोरगुल होगा, और बांग्लादेश टक्कर देगा। रन, विकेट और आतिशबाजी की उम्मीद करें। भारत शुरुआत में प्रबल दावेदार होगा-लेकिन टी20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। गाड़ी स्टार्ट करो!

भारत की संभावित प्लेइंग :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन/जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग :

सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान

क्या भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ जसप्रीत बुमराह को आराम देगा?

मुंबई, 23 सितम्बर। बुधवार को, भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन करेगा, जो 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगी। यह चयन भ्रामक रूप से पेचीदा है, क्योंकि भारत पहली बार आर अश्विन के संन्यास का पूरा असर महसूस करने वाला है (उन्होंने अपने करियर के दौरान भारत के 65 घरेलू टेस्ट मैचों में से एक भी नहीं छोड़ा), जसप्रीत बुमराह के कार्यभार को अभी भी प्रबंधित करने की आवश्यकता है, और पिछले साल न्यूजीलैंड से मिली अप्रत्याशित, अभूतपूर्व 3-0 की हार से जुड़े सवाल अभी भी मंडरा रहे हैं। यहां कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अजीत अगरकर की चयन समिति को देना होगा।

बुमराह को चुनें या उन्हें आराम दें?

अहमदाबाद में पहला टेस्ट एशिया कप के फाइनल के चार दिन बाद शुरू होगा, जिसमें भारत के खेलने की शानदार संभावना है। उनकी एशिया कप टीम के चार सदस्य – टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और बुमराह – आमतौर पर घरेलू सीरीज के लिए टेस्ट टीम में चुने जाते हैं, लेकिन उनमें से एक के लिए परिस्थितियाँ सामान्य से बहुत दूर हैं।

बुमराह ने इंग्लैंड में भारत की पिछली टेस्ट सीरीज़ में पांच में से केवल तीन मैच खेले थे, और उनकी पीठ की गंभीर चोटों के इतिहास को देखते हुए, उनकी भागीदारी का यह अनुपात निकट भविष्य में भी जारी रहने वाला है। तो क्या भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों के लिए बुमराह को चुनेगा, या सिर्फ़ एक टेस्ट मैच के लिए? या फिर उन्हें पूरी सीरीज के लिए आराम दिया जाएगा?

एक या दो साल पहले इसी तरह की स्थिति में, भारत को बुमराह को आराम देना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। लेकिन इस समय उनके गेंदबाजी संसाधन उतने मजबूत नहीं हैं जितने उन्हें घरेलू परिस्थितियों में मिलते हैं। अश्विन की अनुपस्थिति एक बड़ी वजह है, हालांकि आप रवींद्र जडेजा, कुलदीप, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे स्पिन आक्रमण की उम्मीद कर सकते हैं। पिछले साल न्यूजीलैंड से मिली हार ने भारत को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया होगा कि वे किस तरह की पिचों पर अपने घरेलू टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं, और संभवत: चौकोर टर्न वाली पिचों की बजाय सपाट पिचों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया होगा जिससे पहली पारी में बड़ा स्कोर बन सके। हालाँकि, इस तरह के किसी भी बदलाव का मतलब तेज गेंदबाज़ों की भूमिका भी बढ़ाना होगा। और अगर बुमराह नहीं होंगे तो भारत को इस मोर्चे पर मुश्किलें आ सकती हैं।

भारत ने मोहम्मद शमी और उमेश यादव (जो लंबे समय से घरेलू टेस्ट मैचों में उनके पसंदीदा तेज गेंदबाज रहे हैं) को धीरे-धीरे बाहर करने का कोई ख़ास असर महसूस नहीं किया है, लेकिन निकट भविष्य में ऐसी स्थिति की कल्पना करना मुश्किल नहीं है जहां उन्हें खाली सतह पर पुरानी गेंद से खेलने के अनुभव और जानकारी की सख़्त जरूरत महसूस हो। मोहम्मद सिराज और आकाश दीप ने मिलकर सिर्फ़ 19 घरेलू टेस्ट मैच खेले हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा ने अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है।

महान अंपायर डिकी का निधन

लंदन, 23 सितम्बर। महान इंग्लिश अंपायर डिकी बर्ड का मंगलवार को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने दो दशकों से ज्यादा लंबे अंपायरिंग करियर में, बर्ड ने 66 टेस्ट और 69 वनडे मैचों में अंपायरिंग की, जिसमें पहले तीन पुरुष वनडे विश्व कप फाइनल भी शामिल हैं। यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब ने एक बयान में कहा, ''डिकी बर्ड ने एक अंतरराष्ट्रीय अंपायर के रूप में एक शानदार करियर का आनंद लिया और खेल के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय अंपायर के रूप में अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया।'' ''अपने शानदार करियर में, उन्होंने 66 टेस्ट मैचों और 69 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की, जिसमें तीन विश्व कप फाइनल भी शामिल हैं – अपनी ईमानदारी, हास्य और बेबाक शैली के लिए खिलाड़ियों और प्रशंसकों, दोनों की प्रशंसा अर्जित की। ''वह यॉर्कशायर क्रिकेट का पर्याय हैं, जहां वह सबसे वफ़ादार समर्थकों में से एक रहे हैं। 2014 में, उन्हें यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस पद को उन्होंने गर्व और विशिष्टता के साथ निभाया। बर्ड ने इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर और लीसेस्टरशायर के लिए खेला, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय अंपायर के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपने घरेलू करियर में, बर्ड ने 93 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिनमें 3314 रन बनाए, और 1973 में अपने अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग करियर की शुरुआत करने से पहले 2 लिस्ट ए मैच भी खेले। उन्होंने 1996 में संन्यास ले लिया, और आखिरी बार भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में अंपायरिंग की थी, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने पदार्पण किया था।

मानव सुथार का पंजा ऑस्ट्रेलिया 9/350

लखनऊ, 23 सितम्बर। ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए के खिलाफ दूसरे अनधिकृत टेस्ट के पहले दिन मंगलवार को अपनी पहली पारी में नौ विकेट पर 350 रन बना लिए। भारत ए की तरफ से मानव सुथार ने पांच विकेट झटके।

अरावली पोलो और मेफेयर पोलो टीमें जीती

जयपुर, 23 सितम्बर। पीपीसी पोलो ग्राउंड पर ऑल स्टार पोलो टीम ओर मेफेयर पोलो टीम के बीच मैच खेला गया जिसमें मेफेयर पोलो टीम ने ऑल स्टार पोलो टीम को 5 के मुकाबले 6 गोल से हराया। मेफेयर पोलो टीम की ओर से सवीर, शमशीर ओर बतिस्ता ने अपनी टीम के लिए 1- 1 गोल किया। वहीं अनय सिंह ने 3 गोल किए। ऑल स्टार पोलो टीम की ओर से डीनो धनखड़ ओर ध्रुवपाल गोदारा ने 2- 2 ओरमतिहास ने अपनी टीम के लिए 1 गोल किया। पीपीसी पोलो ग्राउंड पर अरावली पोलो टीम ओर नेवी कानोता पोलो टीम के बीच मैच खेला गया जिसमें अरावली पोलो टीम ने नेवी कानोता पोलो टीम को 5 के मुकाबले 8 गोल से हराया। अरावली पोलो टीम की ओर से हुर्र अली ने 2, देवेंद्र सिंह ने 1 ओर कुलदीप सिंह ने 5 गोल किए। नेवी कानोता पोलो टीम की ओर से गोंज़ालो यानज़ोन 4 गोल किए ओर सलीम ने 1 गोल किया।

पीकेएल-12 : टाईब्रेकर में जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को हराया, जीत की पटरी पर लौटे

जयपुर, 23 सितंबर। सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 48वें मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स का सामना यू मुंबा से हुआ। निर्धारित समय तक 38-38 से टाई रहने के बाद मैच टाईब्रेकर में गया, जिसमें मेजबान जयपुर ने 6-4 के अंतर से बाजी मार ली। यह मैच वापसी के लिए जाना जाएगा। मुंबा एक समय 10 अंक से पीछे चल रहे थे और फिर उसने वापसी करते हुए न सिर्फ स्कोर बराबर किया बल्कि 10 अंक की लीड बना ली लेकिन फिर जयपुर ने शानदार वापसी करते हुए मैच को टाई करा लिया। मुंबा के लिए संदीप ने 14 अंक के साथ अपना श्रेष्ठ खेल दिखाया जबकि जयपुर के लिए नितिन धनखड़ (14) ने सुपर-10 लगाया। इसके बाद डिफेंस ने डू ओर डाई रेड पर संदीप को लपक स्कोर 31-36 किया और मुंबा को दो खिलाड़ियों तक सीमित किया और फिर नितिन ने उसे आलआउट की ओर धकेला और इसे अंजाम तक लाकर स्कोर 35-37 कर दिया। नितिन ने फिर सुनील को बाहर कर फासला 1 का कर दिया लेकिन संदीप ने इसे फिर 2 का कर दिया।

दिनेश कार्तिक हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए बने टीम इंडिया के कप्तान

हांगकांग, 23 सितंबर। क्रिकेट हांगकांग ने मंगलवार को घोषणा की कि अनुभवी भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक आगामी प्रतिष्ठित हांगकांग सिक्सेस 2025 में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, जो 7 नवंबर से आयोजित किया जाएगा।

अपने विशाल अंतरराष्ट्रीय अनुभव, कुशल नेतृत्व कौशल और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए माने जाने वाले, कार्तिक का कप्तान के रूप में शामिल होना प्रशंसकों को प्रेरित करेगा और टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ाएगा।

इस अवसर पर, क्रिकेट हांगकांग के अध्यक्ष बुर्जी श्रॉफ ने कहा, ''हमें हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए टीम इंडिया के कप्तान के रूप में दिनेश कार्तिक का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। उनका नेतृत्व और अनुभव इस प्रतियोगिता में अपार मूल्य जोड़ेंगे, और हमें विश्वास है कि उनकी उपस्थिति दुनिया भर के प्रशंसकों को इस शानदार क्रिकेट उत्सव का गवाह बनने के लिए आकर्षित करेगी।'' कप्तान के रूप में अपनी नियुक्ति पर, हांगकांग सिक्सेस के लिए टीम इंडिया के कप्तान दिनेश कार्तिक ने कहा, ''हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया का नेतृत्व करना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है, यह एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसका इतिहास इतना समृद्ध और वैश्विक स्तर पर जाना जाता है।

ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी के सामने पेश हुए युवराज सिंह
सोनू सूद से 24 सितंबर को होगी पूछताछ

नई दिल्ली, 23 सितंबर। भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप वनबेट से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष मंगलवार को पेश हुए। सफेद टीशर्ट और जींस पहे 43 वर्ष के युवराज दोपहर बाहर बजे एजेंसी के दफ्तर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने इस हरफनमौला से पूछतछ की ओर धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत उनके बयान दर्ज किए।एक इन्फ्लुएंसर अन्वेशी जैन भी इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुई। ईडी इससे पहले क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धनव, रॉबिन उथप्पा, टीएमसी की पूर्व सांसद और बांग्ला अभिनेत्री मिमि चक्रवर्ती, अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ कर चुका है। अभिनेता सोनू सूद को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

आरसीए अंडर-15 महिला टीम की ओपन चयन ट्रायल आगामी 26-28 को जयपुर में आयोजित करेगा

जयपुर, 23 सितम्बर। आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमावत के अनुसार बीसीसीआई की आगामी अंडर 15 वीमेन राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान टीम के संभावितों के चयन हेतु आरसीए द्वारा आयोजित की जाने वाली वीमेन अंडर 15 प्रतियोगिता हेतु आरसीए आगामी 26 से 28 सितम्बर 2025 को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन चयन ट्रायल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित आरसीए अकादमी पर आयोजन किया जायेगा।

चयन ट्रायल में भाग लेने वाली खिलाडियों को कलर्डक्लोथिंगमें आना आवश्यक है। चयन ट्रायल में वो ही खिलाडी भाग ले सकते हैं जिनका जन्म दिनांक 01 /09/ 2010 से 31 /08 /2013 के मध्य हुआ हो। चयन ट्रायल में भाग लेने हेतु खिलाडियों को निम्नलिखित मूल दस्तावेज साथ लाना आवश्यक है :- कंप्यूटर जनित जन्म प्रमाण पत्र (अनिवार्य), बोनाफाइड प्रमाण पत्र (अनिवार्य) पिछले तीन वर्षों की शिक्षा की अंकतालिका (अनिवार्य), आधार कार्ड/ वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/पैन कार्ड। अंडर 19 चयन ट्रायल में वो ही खिलाडी भाग ले सकते हैं जिनका जन्म दिनांक 01 /09/ 2006 या उसके पश्चात हो।

आरसीए द्वारा आयोजित की जाने वाली 3 दिवसीय अंडर 15 वीमेन टीम चयन ट्रायल का विवरण :- दिनांक 26 सितम्बर प्रात: 10 बजे (जिले)। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू। दिनांक 27 सितम्बर प्रात: 10 बजे (जिले) दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझनू, जोधपुर व करौली। दिनांक 28 सितम्बर प्रात: 10 बजे (जिले) कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर, जयपुर।

प्रथम पृष्ठ का शेष

राहुल गांधी की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परतों में साफ नजर आ रही हैं। जब राहुल गांधी की बिहार यात्रा आयोजित की गई थी, तो उसमें आरजेडी और सीपीआई सहित, सभी गैर एनडीए सहयोगियों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन इसके तुरंत बाद, तेजस्वी यादव ने अपनी ''बिहार अधिकार यात्रा'' की शुरुआत अकेले ही कर दी और उन्होंने राहुल गांधी और राज्य के कांग्रेस नेताओं को न्योता देने का सामान्य शिष्टाचार तक नहीं दिखाया।

यात्रा के दौरान और उसके बाद, तेजस्वी के करीबी यह दावा करते रहे हैं कि आरजेडी न सिर्फ सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि तेजस्वी यादव ही निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे।

कांग्रेस की आधिकारिक स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद ही किया जाएगा, हालांकि, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, जो कांग्रेस से अधिक आरजेडी के अधिक निकट माने जाते हैं, जैसे नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे।

राहुल गांधी, आश्चर्यजनक रूप से, इस मुद्दे पर चुप रहे है।

मुद्दा यह है, व्यक्तिगत स्तर पर राहुल गांधी ने ''वोट चोरी'' के मुद्दे पर प्रभावी अभियान चलाया है, लेकिन आरजेडी नेतृत्व कांग्रेस को कोई राजनीतिक स्पेस देने को तैयार नहीं दिख रहा।

2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें

> **■ तेजस्वी ने ''बिहार अधिकार यात्रा'' आरंभ कर रखी है, जिसमें कांग्रेस या उसके नेता आमंत्रित नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में सीडब्ल्युसी बैठक आयोजित की है, 1940 के बाद, और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी ऊँचा है।**

जीती थीं, लेकिन पार्टी का यह आरोप बना रहा कि कांग्रेस को दी गई आधे से ज्यादा सीटें ऐसी थीं, जहाँ जीतना लगभग असंभव था। इस बार, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चाहे सीटों की संख्या घटाई भी दी जाए, लेकिन उन्हें ऐसी सीटें दी जाएँ जहाँ पार्टी का जनाधार मौजूद है।

फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस दोनों अपने-अपने रास्ते पर चल रहे हैं। जहाँ अपने सम्मेलन और बैठकें अलग से कर रही है, वहीं पवन खेड़ा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी जिलों और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर उम्मीदवारों के बायोडाटा इकट्ठा कर लिये हैं। यह रणनीति कुछ हद तक ''घोड़े से पहले गाड़ी'' जैसी लगती है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में ऐसे संभावित उम्मीदवार सामने आ जाएँगे, जिन्हें बाद में टिकट देने से मना करना पड़ेगा।

ट्रंप का ''वीज़ा खेल'' : भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सफाई बस दिखावे की है। मर्चैंट बैंक बेरेनबर्ग के अर्थशास्त्री, अताकान बाकिस्कन ने ''द गार्जियन'' से बात करते हुए कहा, ''वीज़ा को बेहद महंगा बनाकर ट्रंप प्रशासन अमेरिका में वैश्विक प्रतिभाओं के आगमन को हतोत्साहित कर रहा है।'' उन्होंने इस कदम को ''विकास विरोधी नीति'' बताया और कहा कि यह नीति इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और कोडरों को दूर करके उत्पादकता को रोक देगी, खासतौर से भारत से आने वालों को, जो एच-1बी वीज़ा का 70 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा रखते हैं।

बेरेनबर्ग ने हाल ही में अमेरिका की वृद्धि का अनुमान 2 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया और चेताया कि अगर नीति में बदलाव नहीं हुआ तो 1.5 प्रतिशत का आंकड़ा भी जल्द ही ज़्यादा आशावादी लग सकता है। बाकिस्कन ने कहा कि आर्टिफिशल इंटैलिजैंस में कितना भी निवेश कर लिया जाए, लेकिन सख्त इमिग्रेशन नियमों के कारण होने वाली प्रतिभाशाली मानव पूंजी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता।

ब्रोकरेज कंपनी एक्सटीबी की शोध निदेशक कैथलीन ब्रूक्स ने बताया कि एमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और गूगल, एच-1बी वीज़ा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में हैं। उनके अनुसार, बड़ी कंपनियां तो शायद यह खर्च सहन कर लेंगी, लेकिन स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्र, जो प्रवासी पेशेवरों पर निर्भर हैं, भर्ती में बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।

भारत के लिए असर वास्तविक होगा, लेकिन सीमित। चूंकि भारतीय नागरिक वीज़ा

> **■ पर, अमेरिका के लिए भारतीय मूल के प्रोफैशनल्स को, जो उनकी जानी-मानी कंपनियों, जैसे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम का नेतृत्व संभाले हुए हैं, उनका विकल्प ढूढ़ना आसान नहीं। साथ ही, इस टैलैंट का अमेरिका में प्रवेश बाधित करके, इस टैलैंट की पाइप लाइन का गला घुट जायेगा, और पाइप लाइन ''चोक'' हो जायेगी।**

प्राप्त करने वालों में सबसे अधिक हैं, इसलिए भारतीय आईटी कंपनियों और पेशेवरों पर शुरुआती झटका पड सकता है। उद्योग संस्था नैसकॉम ने बीबीसी से कहा कि वीज़ा शुल्क में बढ़ोतरी अमेरिका में कुछ ऑनशोर प्रोजेक्ट्स के व्यापारिक संचालन को बाधित कर सकती है, जिससे ग्राहक नए दाम तय करने या काम को, कानूनी स्थिति साफ होने तक, टालने की कोशिश कर सकते हैं। कंपनियां कर्मचारी ढांचे (स्टाफिंग मॉडल) को भी बदल सकती हैं: डिलीवरी को ऑफशोर शिफ्ट करना, ऑनशोर भूमिकाएं कम करना और स्पॉन्सरशिप को सख्त करना।

फिर भी इंफोसिस और टीसीएस जैसी भारतीय आउटसोर्सिंग कंपनियां ऐसे झटकों के लिए पहले से तैयारी कर रही हैं। उन्होंने अमेरिका में स्थानीय कार्यबल तैयार किया है और ऑफशोर डिलीवरी मॉडल मजबूत किए हैं। स्टाफिंग कंपनी सीआईईएल एचआर के आदित्य नारायण मिश्रा ने कहा कि कई फर्में यह अतिरिक्त खर्च अमेरिकी ग्राहकों पर डालने की योजना बना रही हैं और रिमोट कॉन्ट्रैक्टिंग, ऑफशोर कामकाज और फ्रीलांस कर्मचारियों पर ज्यादा भरोसा करेंगी।

आईटी सेक्टर से बाहर भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारत की मौजूदगी बहुत बड़ी है: भारतीय मूल के अधिकारी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के लगभग 6 प्रतिशत डॉक्टर भारतीय हैं। नई प्रतिभाओं की आवक को सीमित करना कई उद्योगों में रुकावटें पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर, जहां भारत व्यवसायिक रणनीतियों और डिलीवरी मॉडल बदलकर इस तत्काल उथल-पुथल से निकल सकता है, वहीं अमेरिका के सामने बड़ा खतरा है, अपने ही विकास इंजन को उस वैश्विक प्रतिभा से काट देना, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाया था।

आरपीएससी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रियदर्शी की नियुक्ति के बाद अब आरपीएससी में दो पूर्व आईपीएस हो गये है। हेमंत प्रियदर्शी रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं। वे इसी साल मई में रिटायर्ड हुए हैं। दूसरे सदस्य डॉ. अशोक कलवार जोधपुर के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तीसरे डॉ सुशील कुमार बिस्सू अजमेर जिले के रहने वाले हैं और मैथमेटिक्स में एमएससी और पीएचडी हैं।

विश्वास नहीं जम पा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और ऐसे उम्मीदवारों को ही वरीयता दी जाए। हालांकि नई प्रणाली के बारीक नियमों और उनके असर को अभी समझना बाकी है, लेकिन पूरे प्रयास ने अनिश्चितता का माहौल बना दिया है।

फिर भी, अचानक की गई इस घोषणा और डॉनल्ड ट्रंप की तीखी बयानबाज़ी ने विदेशी कर्मचारियों-खासतौर से टैक्नॉलजी क्षेत्र में एच-1बी वीज़ा पर काम करने वालों को अनुमति देने की व्यवस्था को नुकसान पहुँचा दिया है। तकनीकी और आईटी क्षेत्र की वे कंपनियां जो इस सुविधा का सबसे अधिक उपयोग करती हैं, अब अमेरिकी संघीय सरकार के बदले हुए रुख को लेकर चिंतित हैं।

उद्योग जगत की अन्य हस्तियों ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। इनमें प्रमुख हैं जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रमुख जेमी डाइमोन। उन्होंने कहा कि उनके दादा स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र लिए बिना ही अमेरिका आ गए थे।

टेस्ला और अन्य कंपनियों के मालिक, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने भी कहा कि वह योजना तेज दिमागों को अमेरिका आने और अपने साथ-साथ अपनाए गए देश के लिए लाभदायक तरीके से काम करने का अवसर देती थी। अमेरिकी सरकार की कुछ आश्वस्त करने वाली बातों के बावजूद माहौल पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है।

संघीय सरकार क्या कदम उठाने वाली है, इस डर को आज 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप के भाषण में लगातार आव्रजन विरोधी रुख ने और पुख्ता कर दिया। उनके शब्दों ने अमेरिका में प्रवास को सीमित करने की उनकी सोच को स्पष्ट कर दिया।

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर ही आरोप लगाया कि वह सीमा पार प्रवासन को प्रोत्साहित कर रहा है और अवैध प्रवासियों को आर्थिक मदद और आवास दे रहा है। उन्होंने अपने हमले का दायरा बढ़ाते हुए यूरोपीय देशों की भी आलोचना की कि वे अवैध प्रवासन के खतरों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ट्रंप ने इन देशों से सीधे कहा कि उनके देश बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं।

डॉनल्ड ट्रंप की आव्रजन और विदेशी कर्मचारियों पर की गई यह बयानबाज़ी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका आईटी क्षेत्र अपने निरंतर कामकाज के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका पर निर्भर है। एच-1बी वीज़ा का लगभग 70 प्रतिशत भारतीय आवेदकों को मिलता है और देश की बडी आईटी सेवा कंपनियां अपने व्यवसाय के लिए पूरी तरह अमेरिका पर टिकी हुई हैं।

भारतीय कंपनियों को जल्द ही वैकल्पिक कामकाज मॉडल ढूँढने होंगे, साथ ही अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों को भी भारतीय प्रतिभा पर अपनी निर्भरता देखते हुए नए रास्ते अपनाने पड़ेंगे। आख़िरकार, यह साझेदारी यूँ ही नहीं बनी थी। यही दक्षता और प्रतिभा का भंडार था जिसने टैक्नॉलजी कंपनियों को उनके प्रदर्शन में नई ऊँचाइयों तक पहुँचने में मदद की।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने हमीरगढ़ में एविएशन अकैडमी का उद्घाटन किया

ड्यूंस एविएशन अकैडमी को राइज़िंग राजस्थान समिट के दौरान भूमि दी गई थी

जयपुर/भीलवाड़ा, 23 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में राजस्थान एविएशन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहां पायलट ट्रेनिंग की विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं के निरंतर विस्तार

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में एविएशन सैक्टर नई ऊँचाइयाँ छू रहा है, जिसका उदाहरण है, कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उदयपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिये 145 एकड़ भूमि की अधिसूचना तथा जयपुर में नये स्टेट टर्मिनल के लिए 12,778 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन।**

से युवाओं के लिए आसमान में अनंत संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे युवाओं को ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ड्यूंस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ड्यूंस एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किया।

एविएशन एकेडमी के उद्घाटन के अवसर पर आमजन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों का हमारी एविएशन पॉलिसी पर दृढ़ विश्वास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइज़िंग राजस्थान समिट के अंतर्गत ड्यूंस एविएशन एकेडमी को भूमि उपलब्ध कराई थी। इस पर जल्द ही फ्लाइंग शुरू भी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान न केवल अपने युवाओं को पायलट बनाएगा, बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए एविएशन की पाठशाला बनेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एविएशन सेक्टर निरंतर नई उचाइयां छू रहा है। इसमें कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह एयरपोर्ट न केवल राजस्थान, बल्कि मध्य भारत के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उदयपुर के एयरपोर्ट विस्तार के लिए 145 एकड़ भूमि के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं, जयपुर के एयरपोर्ट पर नए स्टेट टर्मिनल के निर्माण के लिए 12 हजार 778 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन भी शुरू हो चुका है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, सांसद दामोदर अग्रवाल सहित, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, आमजन एवं ड्यूंस एविएशन एकेडमी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

जगन्नाथ मंदिर का खजाना स्थायी रत्न भंडारों में स्थानांतरित

पुरी, 23 सितंबर। ओडिशा में पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का खजाना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वापस स्थायी रत्न भंडारों में स्थानांतरित कर दिया गया।

मंदिर की एक प्रेस विज्ञिप्त के अनुसार खजाना का स्थानांतरण सुबह 10:55 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2:55 बजे समाप्त हुआ। रत्न भंडारों को स्थानांतरण के बाद बंद करते हुए सील कर दिया गया।

मोहनलाल को दादा साहब फाल्के, शाहरुख व मैसी बैस्ट एक्टर अवॉर्ड से सम्मानित

नयी दिल्ली, 23 सितंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राजधानी में मंगलवार को आयोजित एक समारोह में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण के अन्तर्गत, मलयालय सिनेमा के अप्रतिम कलाकार मोहनलाल को अति प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया।

इस अवसर पर अभिनेता शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। शाहरुख खान ने इस अवार्ड का साझा विक्रांत मैसी के साथ किया। शाहरुख को यह पुरस्कार उनकी फिल्म जवान के लिए तो मैसी को 12वीं फेल के लिए दिया गया। रानी मुखर्जी को मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे फिल्म के लिये सर्वश्रेष्ठ आंका गया।

समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल – ए जैकफ्रूट मिस्ट्री को मिला। यह फिल्म कटहल के चोरी होने और उसकी बरामदगी के बहाने व्यंग्य भरे स्वर में समाज की पड़ताल करती है, जबकि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल को दिया गया। इस फिल्म में गांव के एक सीधे- साधे और बेहद गरीब छात्र के कड़ी मेहनत के बाद भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के लिए चुने जाने की वास्तविक घटना को फिल्माया गया है।

बड़े सपनों का रखें ख़्याल
एलआईसी की
अमृतबाल

एलआईसी की
अमृतबाल
यूआइएन: 512N365V02
प्लान नं. 774

बच्चों के लिये बीमा योजना

LIC/R1/2024-25/17/HIN

प्रॉडक्ट की मुख्य विशेषताएँ
- पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान आकर्षक गारंटीड एडीशन्स
- परिपक्वता की उम्र 18-25 वर्ष
- एकल/सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प

यह प्लान बिक्री के लिये ऑनलाइन भी उपलब्ध है
एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
Har Pal Aapke Saath

LIC मोबाइल ऐप डाउनलोड करें LIC digital | विज़िट करें: licindia.in | कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने शहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें
हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'
हमें यहाँ फ़ॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

नकली फोन कॉल्स और झूठे/धोखाधड़ी पूर्ण ऑफ़र्स से सावधान रहें. आईआरडीएआई जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों के निवेश जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है. ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाएँ. बिक्रि समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़े.

MARUTI SUZUKI
NEXA

CELEBRATIONS JUST GOT BIGGER.
WITH GST BENEFITS + LIMITED PERIOD FESTIVE OFFERS*

	PRICE REDUCTION OF UP TO#	NOW STARTING AT#	ADDITIONAL FESTIVE OFFERS OF UP TO*
FRONX	₹1 12 600	₹6 84 900	₹70 000
GRAND VITARA	₹1 07 000	₹10 76 500	₹1 29 100 + 5 Year Extended Warranty
BALENO	₹86 100	₹5 98 900	₹72 500
IGNIS	₹71 300	₹5 35 100	₹62 500
INVICTO	₹61 700	₹24 97 400	₹1 40 000
XL6	₹52 000	₹11 52 300	₹25 000
JIMNY	₹51 900	₹12 31 500	₹1 00 000

#Prices applicable from 22nd September onwards.

SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU

NEXA SAFETY SHIELD

*FESTIVE OFFERS VALID TILL 30TH SEP ONLY

UP TO 100% WAIVER ON CAR LOAN PROCESSING FEE (ONLY TILL 30TH SEP)##

E-BOOK TODAY @ WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at 1800-200-6392 1800-102-6392

For detailed T&C kindly visit your nearest dealership. Features and accessories shown may not be a part of the standard fitment. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. All offers are brought to you by NEXA dealers only. Offers and features may vary subject to the model and variant purchased. *The mentioned offers include "Consumer Offer + Booking offer + Exchange Bonus + Rural offer", and may vary from city to city. Please contact nearby dealership for more details. Maruti Suzuki reserves the right to withdraw offers at any point in time without any advance notice. All offers are applicable till 30th September '25 or till stocks last. Maruti Suzuki Smart Finance is now available pan India. Maruti Suzuki Subscribe is available only in selected cities. ##Offers include consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offers (wherever applicable) on select models/variants. Finance is at the sole discretion of the financer by selected finance partners.

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908